वर्ष 12 • अंक 297 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शनिवार 1 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6
चीनी उत्पादन पर अलग-अलग दावे

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

"समीक्षा में 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का खाका"

डॉलर रु. 71.40 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 78.70 ▼ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40628 ▼ 56 रुपये | सेंसेक्स 40723.50 ▼ 190.30 | निफ्टी 11962.10 ▼ 73.70 | निफ्टी फ्यूचर्स 11994.30 ▲ 32.20 | ब्रेंट क्रूड 57.40 डॉलर ▼ 0.60 डॉलर

बजट अंक

रविवार 2 फरवरी के अंक में पढ़िए आम बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकली सौगात और कहां लगाई घात। आम लोगों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की बात। आम बजट का संपूर्ण विवरण।

एक नज़र

बुनियादी उद्योगों में सुधार के संकेत

आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर दिसंबर 2019 में 1.3 फीसदी रही। एक साल पहले समान महीने में यह 2.1 फीसदी पर थी। इससे पहले चार महीने तक बुनियादी क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में थोड़ा सुधार हुआ है। कोयला, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक के उत्पादन में सुधार हुआ है, वहीं कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली क्षेत्र पर दबाव देखा गया। स्टील उत्पादन में 1.09 फीसदी और सीमेंट में 5.5 फीसदी की गिरावट आई।

राजकोषीय घाटा लक्ष्य के 132 फीसदी पर पहुंचा

राजस्व संग्रह में कमी की वजह से केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर अंत तक पूरे साल के लिए तय लक्ष्य का 132.4 फीसदी पहुंच गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार वास्तविक तौर पर राजकोषीय घाटा 9,31,725 करोड़ रुपये रहा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान का 58.4 फीसदी रही।

आईटीआई ने फिर बढ़ाई निर्गम की अवधि

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने अपने अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को 5 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। निवेशकों की ठंडी प्रतिक्रिया मिलने की वजह से निर्गम की तिथि आगे बढ़ाई गई है। यह दूसरा मौका है जब कंपनी ने निर्गम की अवधि को बढ़ाया है। इससे पहले 28 जनवरी को कंपनी ने एफपीओ बंद होने की तिथि तीन दिन के लिए बढ़ाई थी। कंपनी ने निर्गम का मूल्य दायरा भी 72 से 77 रुपये से घटाकर 71-77 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। अभी तक इसे 58 फीसदी आवेदन ही प्राप्त हुए हैं।

मालगाड़ियों में सुरक्षा के लिए तैनात होंगे सशस्त्र कर्मी

मालगाड़ियों की सुरक्षा और उनसे सामान की चोरी एवं लूटपाट रोकने के लिए रेलवे पहली बार निजी एजेंसियों के सशस्त्र कर्मियों की तैनाती करने जा रहा है। रेलवे द्वारा जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई। रेलवे की ओर से 29 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार सशस्त्र कर्मियों की तैनाती की मंजूरी सबसे पहले आंशिक तौर पर पूर्वी रेल खंड के लिए दी गई है। इस कदम की छह महीने बाद समीक्षा की जाएगी और फिर अन्य खंड पर इस सेवा की शुरुआत का फैसला लिया जाएगा।

बाजार में गिरावट, अब निगाहें बजट पर

आम बजट से एक दिन पहले शुक्रवार को शेयर बाजारों में गिरावट आई। शेयर बाजार शुरुआती कारोबार में मजबूती के रुख के साथ खुलने के बाद दोपहर में बिकवाली दबाव में आ गए। सेंसेक्स 190.33 अंक के नुकसान से 40,723.49 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 73.70 अंक गिरकर 11,962.10 पर बंद हुआ। पृष्ठ 4

आज का सवाल

क्या आर्थिक सुधारों की दिशा में और कदम उठाएगी सरकार

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या कर संग्रह में कमी का बजट में दिखेगा असर?	हां	83.33%
	नहीं	16.67%

आर्थिक समीक्षा 2019-20

संपत्ति सृजन, सुगमता पर जोर

मिहिर शर्मा
नई दिल्ली, 31 जनवरी

संसद में आज पेश 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में देश में संपत्ति सृजन का एजेंडा रखा गया है और भारत के आर्थिक अनुभव तथा दार्शनिक परंपराओं के आधार पर संपत्ति और व्यापार अनुकूल आर्थिक नीतियां बनाने की मांग की गई है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने समीक्षा की प्रस्तावना में इसकी प्रेरणा का खुलासा किया है। यह प्रेरणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के प्राचीर से दिया गया भाषण। इसमें उन्होंने संपत्ति का सृजन करने वालों के योगदान का जिक्र किया था। उनका कहना था कि जब धन का सृजन होगा तभी तो इसका वितरण होगा। सुब्रमण्यन की दलील है कि उदारीकरण बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की जड़ों की ओर लौटना है। इस तरह उन्होंने समीक्षा में संपत्ति सृजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधारों पर जोर दिया है। वृहद आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो समीक्षा में यह तर्क दिया गया है कि मजबूत जनादेश के कारण सरकार के पास सुधारों पर काम करने की क्षमता है, इसलिए इससे आगे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

- **2020-21 में विकास दर 6 से 6.5 फीसदी रहने का अनुमान**
- **आर्थिक सुस्ती के लिए वैश्विक कारण जिम्मेदार**
- **मांग में कमी से राजकोषीय लक्ष्य हासिल करना मुश्किल**

आधार प्रभाव को देखते हुए समीक्षा में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2020-21 में 6 से 6.5 फीसदी के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। समीक्षा में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आर्थिक सुस्ती को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा तय 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण होगा।

समीक्षा में आर्थिक सुस्ती के लिए मुख्य रूप से वैश्विक कारणों को जिम्मेदार बताया गया है। वैश्विक उत्पादन में गिरावट के कारण 2017 से भारत की जीडीपी वृद्धि प्रभावित हुई है। इसमें हाल में हुए कुछ शोधों के हवाले से कहा गया है कि भारत में कारोबारी चक्र की अवधि 13 तिमाहियों की थी जो मंदी के दौर में शायद तेज थी। इसके मद्देनजर समीक्षा में अनुमान लगाया गया है कि 2019-20 की मौजूदा छमाही में आर्थिक विकास दर पटरी पर लौटेगी।

समीक्षा में यह तर्क भी दिया गया है कि 2011-12 और 2017-18 के बीच निजी कॉरपोरेट निवेश जीडीपी के करीब 11.5 फीसदी पर स्थिर रहा। विकास की धीमी गति और खासकर जीडीपी तथा खपत में हाल में आई गिरावट को इससे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। निजी कॉरपोरेट निवेश में इस ठहराव का बैंकों की ऋण वृद्धि में गिरावट के साथ संबंध है। समीक्षा में कहा गया है कि मांग और उपभोक्ताओं की धारणा में सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अगर सरकार राजकोषीय लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती है, तो यह वाजिब है।

सुधारों की वकालत करते हुए समीक्षा में कहा गया है कि देश में संपत्ति सृजन को बढ़ावा देना अर्थव्यवस्था में सरकार के अनावश्यक और प्रतिकूल हस्तक्षेप का खात्मा है। समीक्षा में आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए का हवाला देते हुए कहा गया है कि शोधों से पता चला है कि भंडारण सीमा लगाने का पिछले साल प्याज की कीमतों पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ईसीए के तहत 76,000 छापे मारे गए जिनमें से केवल 4 फीसदी मामलों में ही सजा हुई। इस तरह ईसीए का नतीजा यह हुआ कि इससे व्यापारियों को परेशानी हुई।

आर्थिक समीक्षा पर विशेष पृष्ठ : 2, 3 और 4

फोटो : संजय शर्मा

"आर्थिक वृद्धि दर में जितनी नरमी हो सकती थी वह हो चुकी है और अब आगे इसमें सुधार दिखेगा।"

केवी सुब्रमण्यन
मुख्य आर्थिक सलाहकार

जीडीपी का लेखाजोखा

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा आईएमएफ

कर्ज मांग में कमी (फीसदी में)

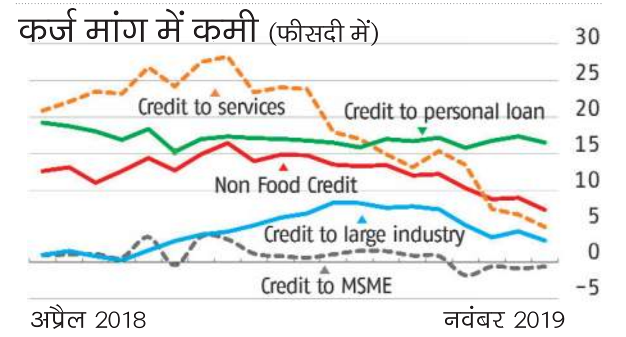

नोट : 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से क्षेत्रवार कर्ज वृद्धि के आंकड़े। स्रोत : आरबीआई

स्थानीय उत्पादों की खरीद से सुदृढ़ होगा देश

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 31 जनवरी

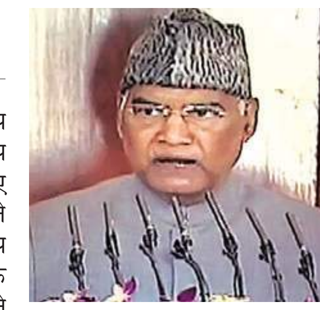

रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति

- **बेहतर भविष्य के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद को आंदोलन बनाने पर दिया जोर**
- **वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत**
- **विपक्षी सांसदों ने सीएए के विरोध में काली पट्टी बांधी, बैनर भी दिखाए**

आजादी के बाद के लोकप्रिय नारे 'भारतीय बनो, भारतीय खरीदो' को नया कलेवर देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 'बेहतर भविष्य के लिए स्थानीय उत्पाद खरीदने' को एक आंदोलन के रूप में तब्दील करने का आह्वान किया है।

राष्ट्रपति ने बजट सत्र की शुरुआत में अपना अभिभाषण देते हुए हरेक भारतीय से स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। कोविंद ने कहा, 'स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल कर आप अपने इलाके में मौजूद छोटे उद्यमियों की बड़ी मदद करेंगे।' उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत आजादी का बुनियादी मंत्र रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। हालांकि उन्होंने इस लक्ष्य के लिए कोई समयसीमा नहीं रखी है जबकि अब तक सरकार इसके लिए 2024 की सीमा देती रही है। वैसे आर्थिक समीक्षा में इस लक्ष्य के लिए वर्ष 2025 की समयसीमा बताई गई है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नागरिकता कानून को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का भी असर दिखा। राष्ट्रपति ने नागरिकता कानून को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि विरोध के नाम पर हिंसा से समाज और देश कमजोर होगा। सीएए का जिक्र होते ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद सीएए-एनआरसी विरोधी बैनर लेकर खड़े हो गए। वहीं सत्तारूढ़ राजग के सांसद करीब आधे मिनट तक तालियां बजाते रहे। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) के विरोध में अपनी बांह पर काली पट्टियां बांधी थीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनियां गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने अगली कतार में आवंटित सीट पर बैठने से मना कर दिया और अपने सांसदों के साथ पांचवीं कतार में बैठे। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछली कतार में आने के अनुरोध को अनसुना कर दिया।

बहरहाल राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्त्व मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम एवं छोटे शहर नई आर्थिक भूमिका में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दशक में दुनिया एक समावेशी, समृद्ध, समर्थ एवं सशक्त 'न्यू इंडिया' देखेगी लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई तय समय नहीं बताया। अपने अभिभाषण में उन्होंने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फायदा होने की बात भी कही।

एसबीआई: उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन

दिसंबर तिमाही में एसबीआई की शुद्ध ब्याज आय 22 फीसदी बढ़कर 27,779 करोड़ रुपये रही

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का प्रदर्शन चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर रहा। इस अवधि के दौरान ज्यादातर परिचालन मानकों पर बैंका का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत रहा। हालांकि कमजोर आर्थिक हालात की वजह से ऋण आवंटन में जरूर सुस्ती दिखी। आलोच्य अवधि में सालाना आधार पर बैंक की शुद्ध ब्याज आय 22.42 प्रतिशत बढ़कर 27,779 करोड़ रुपये हो गई। इसी तरह, बैंक का कर पूर्व मुनाफा भी सालाना आधार पर 65.74 प्रतिशत बढ़कर 10,970 करोड़ रुपये हो गया। कॉर्पोरेट दर में कटौती के दम पर शुद्ध मुनाफा भी 41.18 प्रतिशत उछलकर 5,583 करोड़ रुपये रहा। एस्सार स्टील ऋण खाते से अच्छी खासी रकम वापस मिलने से बैंकों को बेहतर आंकड़े दर्ज करने में मदद मिली, डीएचएफएल ऋण खाता एनपीए में तब्दील होने से बैंक का लाभ सीमित रह गया।

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि तीसरी तिमाही में सभी मानदंडों पर बैंक का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। उन्होंने कहा, 'डीएचएफएल ऋण खाता एनपीए में तब्दील हो गया, जिससे परेशानी हुई। हालांकि तीसरी तिमाही में एक बड़ी इस्पात कंपनी (एस्सार स्टील) से 11,000 करोड़ रुपये वसूली होने से काफी मदद मिली।' बैंक के कॉर्पोरेट ऋण खाते में सालाना आधार पर 0.48 प्रतिशत गिरावट आई। पृष्ठ 11

एचयूएल का कर पूर्व लाभ बढ़ा

देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तु कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) ने अपने आंकड़ों से शुक्रवार को बाजार को चकित कर दिया। चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी की बिक्री में 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज हुई। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव मेहता ने कहा कि कठिन आर्थिक हालात के बीच कंपनी ने ये आंकड़े दर्ज किए गए हैं। एचयूएल की तीसरी तिमाही का आंकड़ा पूरे एफएमसीजी क्षेत्र की कुल 2 प्रतिशत बिक्री से अधिक रहा।

आलोच्य अवधि में एचयूएल का कर पूर्व मुनाफा सालाना आधार पर 14.3 प्रतिशत तेजी के साथ 2,229 करोड़ रुपये रहा। इसी तरह, शुद्ध मुनाफा एक साल पहले के मुकाबले 12 प्रतिशत बढ़कर 1,616 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का राजस्व भी 2.6 प्रतिशत बढ़कर 9,808 करोड़ रुपये हो गया। ब्लूमबर्ग के अनुसार विश्लेषकों ने यह आंकड़ा 10,034 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया था। मेहता ने कहा कहा कि निकट अवधि में मांग की हालत चुनौतीपूर्ण दिख रही है। हालांकि उन्होंने कहा नीतिगत उपायों को लेकर वह आशान्वित हैं और उन्हें लगता है कि इससे मांग एवं उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच, एचयूएल ने कहा कि पाम तेल की बढ़ती लागत की वजह से कंपनी साबुन के दाम 6 फीसदी तक बढ़ाएगी।

बीएस संवददाता

भारतीयों को लाने चीन भेजा गया विमान

चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित वुहान शहर से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एयर इंडिया का 423 सीटों वाला बी747 विमान शुक्रवार को अपराह्न एक बजकर 20 मिनट पर दिल्ली से रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि विमान में राममनोहर लोहिया अस्पताल के पांच चिकित्सक और एक पैरामेडिकल कर्मी सवार थे। इसके जरिये करीब 400 भारतीयों को वापस लाने की संभावना है। एक अन्य विशेष उड़ान शनिवार को दिल्ली से रवाना हो सकता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने वायरस से प्रभावित संदिग्धों के लिए दिल्ली में 600 बिस्तरों वाला केंद्र तैयार किया है। इस बीच सरकार ने मास्क के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है ताकि घरेलू बाजार में इसकी किल्लत न हो। पृष्ठ 14

अरविंद के हाथ आईबीएम की कमान

नेहा अलावधी और देवाशिष महापात्र
नई दिल्ली/बेंगलूरु, 31 जनवरी

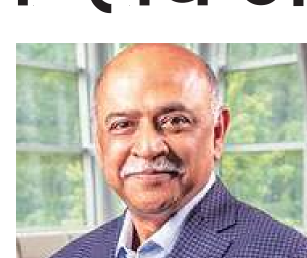

अरविंद कृष्ण

दिग्गज कंपनियों में भारतीय मूल के मुख्य कार्याधिकारी

- **2 अक्टूबर,** 2015 को सुंदर पिचई बने गूगल के सीईओ
- **4 फरवरी,** 2014 को माइक्रोसॉफ्ट ने सत्य नाडेला को सीईओ बनाया
- **1 दिसंबर,** 2007 को एडोबी के सीईओ बने शांतनु नारायण
- **1 जुलाई,** 2010 को मास्टरकार्ड ने अजय सिंह बंगा को सीईओ नियुक्त किया

दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी इंटरनैशनल बिजनेस मशीन्स (आईबीएम) ने भारतीय मूल के अरविंद कृष्ण को अपना अगला मुख्य कार्याधिकारी बनाने की घोषणा की है। यह भारतीय आईटी उद्योग के लिए एक और कीर्तिमान है।

कृष्ण 6 अप्रैल को आईबीएम का जिम्मा संभालेंगे। वह वर्ष 2012 से ही मुख्य कार्याधिकारी का जिम्मा संभाल रहीं वर्जीनिया रोमैटी की जगह लेंगे। रोमैटी इस साल के अंत तक कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी चेयरमैन बनी रहेंगी और करीब 40 साल सेवा देने के बाद कंपनी से सेवानिवृत्त होंगी।

रोमैटी ने कहा, 'आईबीएम की अगली पीढ़ी के लिए अरविंद उपयुक्त सीईओ हैं। वह बेहतरीन प्रौद्योगिकीविद हैं और कंपनी की मुख्य प्रौद्योगिकियों - कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचैन आदि के विकास में अहम भूमिका निभाई है।' उन्होंने कहा कि अरविंद ने आईबीएम के क्लाउड और सॉफ्टवेयर कारोबार का विस्तार किया है तथा कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े अधिग्रहण की अगुआई की है। सबसे बड़े अधिग्रहण से यहां रेड हैट को खरीदने से है। आईबीएम ने 2018 में 34 अरब डॉलर में इस सॉफ्टवेयर फर्म का अधिग्रहण किया था। 57 वर्षीय अरविंद करीब 29 साल से आईबीएम के साथ हैं। 1985 में आईआईटी कानपुर से स्नातक और इलिनॉय विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के बाद 1990 में उन्होंने आईबीएम ज्वॉइन की थी। वह वर्तमान में आईबीएम में क्लाउड तथा कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं।

अरविंद कृष्ण दुनिया की अग्रणी आईटी फर्मों की कमान संभाल रहे दिग्गज भारतीय मुख्य कार्याधिकारियों की जमात में शामिल हो गए हैं।

(शेष पृष्ठ 14 पर)

नीमचवाला का विप्रो से इस्तीफा

आईटी कंपनी विप्रो के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक आबिदअली जेड नीमचवाला ने पारिवारिक प्रतिबद्धताओं की वजह से इस्तीफा देने का फैसला किया है। विप्रो ने बताया कि 52 वर्षीय नीमचवाला तब तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक उनकी जगह पर कोई नई नियुक्ति नहीं हो जाती है। इससे कंपनी का कामकाज प्रभावित नहीं होगा। कंपनी ने बताया कि नीमचवाला ने पारिवारिक कारणों से पद से हटने का निर्णय लिया है। कंपनी बोर्ड ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है।

उठाएं सुधारों की दिशा में साहसिक कदम

प्रतिक्रिया | उद्योग मंडलों व आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक 6.5 प्रतिशत वृद्धि चुनौतीपूर्ण

भाषा
नई दिल्ली, 31 जनवरी

उद्योग मंडलों और आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि 2020-21 में 6 से 6.5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। उनका कहना है कि सरकार को वृद्धि को प्राथमिकता देने की जरूरत है और इसे हासिल करने के लिए साहसिक उपाय करने होंगे।

संसद में आज पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर 6 से 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके 5 प्रतिशत रहने की संभावना है।

उद्योग मंडल सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजित बनर्जी ने कहा, 'वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा में वृद्धि दर 6 से 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है। इस लक्ष्य को उपयुक्त सुधारों और सार्वजनिक निवेश के जरिए हासिल किया जा सकता है।' सीआईआई ने कहा कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि आम बजट में क्या हो सकता है। इसके आधार पर उम्मीद है कि बजट में कुछ साहसिक सुधार देखने को मिल सकता है।

पीडब्ल्यूसी इंडिया के आर्थिक परामर्श सेवा प्रमुख रानेन बनर्जी ने कहा कि 6 से 6.5 प्रतिशत वृद्धि हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, 'देश में मांग में अभी तेजी आनी बाकी है। भारत समेत वैश्विक वृद्धि पर कोरोना विषाणु का प्रभाव देखने को मिल सकता है।'

डेलायॅट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि समीक्षा में 2020-21 में आर्थिक वृद्धि में तेजी की बात कही गई है लेकिन इसमें यह भी कहा है कि सरकार को वृद्धि में तेजी लाने के लिए खर्च बढ़ाना पड़ सकता है। यानी राजकोषीय घाटा बढ़ेगा।

उन्होंने कहा, 'जैसा कि पहले भी कहा गया है, सरकार को फिलहाल आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक बार इसमें तेजी आती है, सरकार अपने व्यय को काबू में करने के लिए कदम उठा सकती है।'

उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि केंद्र सरकार को आर्थिक वृद्धि में तेज करने के लिए साहसिक नीतिगत और राजकोषीय उपाय करने की जरूरत है।

केपीएमजी में पार्टनर और राष्ट्रीय प्रमुख (बुनियादी ढांचा, सरकार और स्वास्थ्य) ए जार्ज ने कहा, 'आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को हकीकत में बदलने और राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न केवल बुनियादी ढांचा और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश की जरूरत है बल्कि भरोसे का एक माहौल भी बनाने की आवश्यकता है।

ज्यादा दखल से वृद्धि पर दबाव

घटे हस्तक्षेप | अनिवार्य जिंस अधिनियम, दवा कीमत नियंत्रण, कृषि ऋण माफी और अनाज बाजारों को स्वायत्तता न देने जैसी दखलंदाजी से संपत्ति निर्माण में बाजारों की क्षमता प्रभावित होती है

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 31 जनवरी

निवेश और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए आर्थिक समीक्षा में पुराने सरकारी हस्तक्षेपों को समाप्त किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। समीक्षा में कहा गया है कि इस तरह के हस्तक्षेप मददगार साबित होने के बजाय नुकसानदायक होते हैं।

इसमें कहा गया है कि अनिवार्य जिंस अधिनियम (ईसीए), दवा कीमत नियंत्रण, कृषि ऋण माफी और अनाज बाजारों में स्वायत्तता प्रदान नहीं करने जैसी सरकार की दखलंदाजी से संपत्ति निर्माण में मदद के लिए बाजारों की क्षमता प्रभावित होती है।

समीक्षा में कहा गया है, 'सरकार में प्रत्येक विभाग और मंत्रालय को उन क्षेत्रों की व्यवस्थित ढंग से जांच करनी चाहिए जहां सरकार ने गैर-जरूरी हस्तक्षेप किया है और बाजारों को कम आंका है। ऐसे हस्तक्षेप को दूर किए जाने से बाजारों को प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी और इससे निवेश तथा आर्थिक वृद्धि में मजबूती आएगी।'

ईसीए को लेकर समीक्षा में कहा गया है कि जिंसों पर स्टॉक सीमा लगाने से न तो कीमतें नीचे आती हैं और न ही कीमतों में अस्थिरता दूर होती है। इसके बजाय, इससे निजी क्षेत्र द्वारा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों पर प्रभाव पड़ता है।

ताजा प्याज संकट का उदाहरण देते हुए समीक्षा में कहा गया है कि सितंबर 2019 में स्टॉक सीमा थोपे जाने से खुदरा और थोक बिक्री कीमतों में अस्थिरता बढ़ी। प्याज में खुदरा महंगाई दिसंबर में 300 प्रतिशत को पार कर गई थी।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, 'उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या आज के भारत में ईसीए जरूरी है।' इसी तरह, ड्रग (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 से गैर-नियमित दवाओं की तुलना में नियंत्रित दवाओं की कीमतों में तेजी को बढ़ावा मिला। इसमें कहा गया है कि कीमतों में वृद्धि कई महंगे फॉर्मूलेशनों के लिए सस्ते, और खुदरा दुकानों के बजाय अस्पतालों में बेचे जाने वाले फॉर्मूलेशन की तुलना में काफी अधिक है। आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों के अनुसार, डीपीसीओ से सस्ते फॉर्मूलेशनों के लिए कीमतों में 21 प्रतिशत की वृद्धि को बढ़ावा मिला। हालांकि, महंगे फॉर्मूलेशनों के मामले में, कीमत वृद्धि लगभग 2.4 गुना थी।

समीक्षा के अनुसार, 'सरकार दवाओं की बड़ी खरीदार होने के नाते अपनी सभी खरीदारियों के समावेश और अपनी मोलभाव की क्षमता का इस्तेमाल कर किफायती दवाएं मुहैया कराने के लिए ज्यादा प्रभावी तरीके से हस्तक्षेप कर सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को गैर-दबाव वाली प्रणालियां विकसित करनी चाहिए जिनका इस्तेमाल सरकार की मूल्य निर्धारण क्षमता में पारदर्शी तरीके से किया जा सके।'

उन क्षेत्रों की जांच हो, जहां सरकार ने गैर जरूरी हस्तक्षेप किया है

आर्थिक समीक्षा में सात अधिनियमों को समाप्त करने या इनमें संशोधन किए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया है, जिनमें फैक्टरीज ऐक्ट, ईसीए,1995, भारतीय खाद्य निगम, 1965, सिक टेक्सटाइल्स अंडरटेकिंग्स (नैशनलाइजेशन) ऐक्ट, 1974, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टु बैंक्स एंड फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐक्ट और द राइट टु फेयर कम्पनसेशन ऐंड ट्रांसपरेंसी इन लैंड एक्यूजीशन, रीहैब्लिटेशन ऐंड रीसेटलमेंट ऐक्ट शामिल हैं।

राइट टु फेयर कम्पनसेशन ऐंड ट्रांसपरेंसी इन लैंड एक्यूजीशन, रीहैब्लिटेशन ऐंड रीसेटलमेंट ऐक्ट को वर्ष 2013 में पेश किया गया था जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है।

एकीकरण के साथ पूरे हों सतत विकास लक्ष्य

एकीकरण | बुनियादी ढांचा व सामाजिक सुधार को एक साथ लाने का प्रस्ताव

श्रेया जय
नई दिल्ली, 31 जनवरी

सामाजिक-आर्थिक पहल के एकीकरण का आह्वान करते हुए आर्थिक समीक्षा 2019-20 ने सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक सुधार को एक साथ लाने का प्रस्ताव दिया है। 'सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एकीकरण' का सुझाव देते हुए इसमें कहा गया कि इस एकीकरण से कई नीतियों तथा उनका कार्यान्वयन मजबूत होगा।

समीक्षा में कहा गया, 'कई सतत विकास लक्ष्यों के कुछ उद्देश्य एक समान होते हैं और इनको हासिल करने के लिए बनाई गई नीतियों पर ध्यान देकर इनकी लिंकेज की पहचान करनी चाहिए। साथ ही, इन लिंकेज की पहचान करके संभावित लेनदेन (ट्रेडऑफ) की पहचान करनी चाहिए जो लक्ष्यों के तहत निर्धारित प्रायोजन को हासिल करने को सीमित कर सकती है।'

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2015 में एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। इसमें स्वच्छ जल एवं साफ-सफाई, सस्ती तथा स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग नवाचार एवं बुनियादी ढांचा, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय एवं सामाजिक संस्थाएं, भुखमरी को समाप्त करना और महिला-पुरुष समानता शामिल हैं।

समीक्षा में स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक पहुंच को बिजली की आपूर्ति के साथ परस्पर जोड़ने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया, 'यह देखा गया है कि बिजली की मदद से स्कूलों में आधुनिक तौर तरीके विकसित करने तथा बेहतर शिक्षण सामग्रियों की मदद से छात्रों के समग्र विकास तथा सीखने के प्रति उनके आकर्षण को बढ़ाने में मदद मिलती है।'

आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि कम साक्षरता दर वाले राज्यों के स्कूलों में बिजली की उपलब्धता भी कम है और इसके विपरीत अधिक साक्षरता वाले राज्यों के स्कूलों में तुलनात्मक रूप से अधिक बिजली आती है। बाल चिकित्सा देखभाल, नवजात आपातकालीन सेवाएं तथा सफल टीकाकरण जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।

इसमें कहा गया, 'देश में विद्युत उपभोग के साथ नवजात बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट के बीच सकारात्मक संबंध देखा गया है।' समीक्षा में स्कूलों के विद्युतीकरण तथा छात्रों के नामांकन में संबंध दर्शाने के लिए कई राज्यों के आंकड़ों को शामिल किया है। मानव विकास सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में विद्युतीकरण तथा स्कूल नामांकन में सकारात्मक संबंध देखा गया है।

राजकोषीय लक्ष्यों में दिखेगी सुगमता

बेहतर की आस | वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी वृद्धि 6 से 6.5 फीसदी रहने का अनुमान, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से आर्थिक वृद्धि रफ्तार पकड़ेगी और आगामी वर्ष के लिए तेजी जारी रहेगी

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 31 जनवरी

आर्थिक समीक्षा 2019-20 में अनुमान जाहिर किया गया है कि 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 6 से 6.5 फीसदी रहेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से आर्थिक वृद्धि रफ्तार पकड़ेगी और आगामी वर्ष के लिए तेजी जारी रहेगी।

समीक्षा में यह भी कहा गया है कि इस वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में नरमी लानी होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2020-21 को किए जाने से महज एक दिन पहले जारी आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, 'अर्थव्यवस्था में वृद्धि को पटरी पर लाने के संबंधी सरकार की त्वरित प्राथमिकता के मद्देनजर आगे चलकर चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में थोड़ी कमी की जा सकती है।'

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन और उनकी टीम द्वारा तैयार आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, 'वृद्धि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि में तेजी आनी चाहिए। इसका एक कारण 2019-20 में 5 फीसदी वृद्धि का तुलनात्मक आधार कमजोर होना है। तेजी एवं नरमी संबंधी जोखिमों के शुद्ध आकलन के आधार पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 6 से 6.5 फीसदी के दायरे में रहने का अनुमान है।'

बिजनेस स्टैंडर्ड ने दिसंबर में सबसे पहले इन आंकड़ों का उल्लेख किया था।

जीडीपी वृद्धि के लिए आर्थिक समीक्षा का अनुमान विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा 2020-21 में भारत के लिए जारी अनुमानों से अधिक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक ने आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 5.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया था। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) के लिए जीडीपी वृद्धि 5.9 फीसदी से 6.3 फीसदी के दायरे में रहने का अनुमान जाहिर किया था।

वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में की जा सकती है कमी

समीक्षा में नरमी एवं तेजी संबंधी तमाम जोखिमों का उल्लेख किया गया है जिससे वृद्धि प्रभावित हो सकती है। जीडीपी अनुमान के नरमी संबंधी जोखिमों में पश्चिम एशिया में जारी तनाव एवं कच्चे तेल की कीमतों पर उसका प्रभाव, व्यापार संबंधी तनाव, दिवालिया प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार और नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में भारी सार्वजनिक निवेश आदि का उल्लेख किया गया है। जबकि तेजी संबंधी अनुमानित जोखिमों में निर्यात गतिविधियों में तेजी, अनुकूल वैश्विक धारणा, कॉरपोरेट कर में कटौती का प्रभाव और मेक इन इंडिया पर जोर आदि शामिल हैं।

समीक्षा में कहा गया है कि शुद्ध रूप से ऐसा लगता है कि मजबूत जानदेश वाली सरकार के पास सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने की क्षमता को देखते हुए वृद्धि के ऊपर जाने की संभावना अधिक है।

राजकोषीय मोर्चे पर समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए कर राजस्व बजट 2019-20 के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले थोड़ा कम रहेगा। कम कर प्राप्तियों के कारण पैदा हुए इस अंतर की कुछ हद तक भरपाई अधिक गैर-कर राजस्व और विनिवेश प्रक्रिया से किया जा सकता है जो लंबी अवधि के लिहाज से टिकाऊ रणनीति नहीं है।

हालांकि समीक्षा में कर राजस्व के लिए किसी आंकड़े का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस साल कर राजस्व में 1.5 लाख करोड़ रुपये की कमी आ सकती है।

समीक्षा में कहा गया गया हहै कि व्यय में खासकर पूंजीगत व्यय में किसी भी कटौती से वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसमें कहा गया है, 'सरकार को सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा घरेलू मांग में तेजी लाना भी वृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण है। जबक चालू वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम की जा सकती है।'

जीडीपी की आलोचना का कोई अर्थ नहीं

गणना | गणना के तरीके में बदलाव के बाद भी संकेतकों व जीडीपी के बीच संबंध बना हुआ है और जीडीपी अनुमान का पुनरीक्षित तरीका सही है। जीडीपी के गलत अनुमान की चिंता की कोई वजह नहीं

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 31 जनवरी

आर्थिक समीक्षा में भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना को लेकर हो रही आलोचकों की चिंता को खारिज करते हुए कहा गया है कि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके एक अध्याय 'क्या भारत की जीडीपी वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया? नहीं!' में कहा गया है, 'भारत की जीडीपी वृद्धि के गलत अनुमान लगाए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।'

इस मसले को तब महत्त्व मिला जब समीक्षा के लेखक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन के पूर्ववर्ती अरविंद सुब्रमण्यन ने मौजूदा तरीकों में खामियां पाई थीं जिसमें मूल्यवर्धन के तरीके में बदलाव के साथ 2011-12 को नया आधार माना गया है। अरविंद ने अपने एक शोधपत्र में कहा था कि भारत और कई देशों के तमाम साक्ष्यों से पता चलता है कि भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 2011 के बाद हर साल करीब 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर दिखाई गई है।

इसी तरह की आलोचना अन्य विशेषज्ञों ने भी की थी। बहरहाल कृष्णमूर्ति की समीक्षा में कहा गया है कि जो मॉडल 2011 के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान में 2.77 प्रतिशत के गलत तरीके से अधिक अनुमान की बात करते हैं, वे नमूने में शामिल 51 देशों के मामले में जीडीपी वृद्धि का गलत अनुमान व्यक्त करते हैं। इस अवधि के दौरान ही 51 देशों की जीडीपी वृद्धि के बारे में गलत अनुमान लगाकर 4 प्रतिशत से -4.6 प्रतिशत के बीच रखा गया है। इस गलत वृद्धि अनुमान में अमेरिका की जीडीपी का 1.6 प्रतिशत, जर्मनी का 1 प्रतिशत, सिंगापुर का -2.3 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका का -1.2 प्रतिशत और बेल्जियम का -1.3 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान शामिल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रकाशित पेपर में अरविंद ने कहा है कि खासकर विनिर्माण के बारे में सबसे गलत अनुमान लगाया गया। उन्होंने कहा कि 2011 के पहले विनिर्माण मूल्यवर्धन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के विनिर्माण घटक और विनिर्माण निर्यात से जुड़ा रहता था। उन्होंने कहा कि लेकिन इसके बाद हुए बदलाव से औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में आकलन प्रभावित हुआ है।

सुब्रमण्यन बनाम सुब्रमण्यन बना था मामला

पूर्व सीईए ने जीडीपी की गणना के नए तरीके को निर्यात, आयात उद्योग को मिले वास्तविक कर्ज, पेट्रोलियम की खपत, रेलवे माल ढुलाई, बिजली की खपत आदि से भी जोड़ा है। समीक्षा में कहा गया है कि ये मानक गैर स्थिरता के लिए कुख्यात रहे हैं। इनका असर न सिर्फ 1980 से 2015 के बीच हर 3 या 5 साल के बाद बदलने के संकेत देता रहा है, बल्कि समय बीतने के बाद इनके मूल्यों में अहम बदलाव आए हैं।

जिला स्तर पर जीडीपी में बदलाव का उल्लेख

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 31 जनवरी

आर्थिक समीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि जीडीपी के नए तरीके के किसी विश्लेषण में जिला स्तर पर होने वाले आर्थिक बदलाव को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि साक्ष्यों से पता चलता है कि नई फर्मों के सृजन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी से जिला स्तर पर जीडीपी में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

औपचारिक क्षेत्र में नई फर्मों का सृजन 2014 के बाद उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जिसका असर जिला स्तर की वृद्धि पर पड़ा और उसके बाद निश्चित रूप से किसी भी विश्लेषण में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि में इसे शामिल किया जाना चाहिए। एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए इसमें कहा गया है कि पोषण और बिजली जैसे संकेतकों में सुधार से कहा जा सकता है कि तरीके में बदलाव के बाद भारत के जीडीपी की वृद्धि दर ज्यादा रही है। इसके साथ ही नई फर्मों के सृजन के साक्ष्य से यह पता चलता है कि सेवा क्षेत्र में नई फर्मों का सृजन विनिर्माण, बुनियादी ढांचा या कृषि से ज्यादा रहा है। सूक्ष्म स्तर का यह साक्ष्य पूरी तरह से व्यापक स्तर के तथ्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के महत्त्व को दिखाया गया है।

समीक्षा में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भारत के सांख्यिकीय बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कहा गया है, 'इस संदर्भ में पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद (प्रणव सेन) की अध्यक्षता में 28 सदस्यों की समिति का गठन अहम है।'

सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों में निजीकरण पर जोर

निजीकरण | सूचीबद्ध कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी एक अलग कंपनी को हस्तांतरित करना चाहिए। कंपनियों का प्रबंधन एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा होना चाहिए और एक समयावधि के दौरान सूचीबद्ध सीपीएसई में सरकार की हिस्सेदारी का विनिवेश कर देना चाहिए

सोमेश झा
नई दिल्ली, 31 जनवरी

मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के आक्रामक निजीकरण के लिए रास्ता साफ करते हुए सुझाव दिया है कि सरकार को सूचीबद्ध कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी एक अलग कंपनी को हस्तांतरित करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि कंपनियों का प्रबंधन एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा होना चाहिए और एक समयावधि के दौरान सूचीबद्ध सीपीएसई में सरकार की हिस्सेदारी का विनिवेश कर देना चाहिए।

सुब्रमण्यन और उनकी टीम द्वारा तैयार आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, 'इससे विनिवेश प्रक्रिया के लिए पेशेवर दृष्टि और स्वायत्ता आएगी जिससे सीपीएसई के आर्थिक प्रदर्शन में सुधार होगा।' उन्होंने कहा कि सरकार को टेमासेक होल्डिंग्स कंपनी के अनुभव से सीख सकती है जो सिंगापुर सरकार की स्वामित्व वाली कंपनियों के निवेश का प्रबंधन करने वाली एक निजी कंपनी है।

समीक्षा में कहा गया है, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिन चुनिंदा सीपीएसई में विनिवेश के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी है उनमें विनिवेश की प्रक्रिया आक्रामक होनी चाहिए क्योंकि इससे लाभप्रदता में सुधार होगा, कुशलता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर होगी और प्रबंधन के पेशेवर नजरिये में सुधार होगा।'

समीक्षा में कहा गया है कि रणनीतिक विनिवेश के तहत मुख्य तौर पर गैर-रणनीतिक कारोबार से बाहर होने और इन सीपीएसई की आर्थिक क्षमता को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है ताकि सरकार इस रकम का इस्तेमाल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में कर सके। सुब्रमण्यन ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की उन 33 इकाइयों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो 2016 से ही रणनीतिक बिक्री के इंतजार में हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने उन 11 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का एक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जिनका रणनीतिक विनिवेश 1999-2000 और 2003-04 के दौरान किया गया था। इसमें दर्शाया गया है कि निजीकरण के बाद इन कंपनियों के आर्थिक प्रदर्शन के सभी संकेतकों में सुधार हुआ है। यह विश्लेषण निजीकरण से पहले और बाद के 10 वर्षों की अवधि पर आधारित है। साथ ही समान उद्योग की अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के प्रदर्शन के साथ भी उनकी तुलना की गई है।

सरकारी कंपनियों को आक्रामक तरीके से बेचने का सुझाव

समीक्षा में कहा गया है, 'इस रुझान से साबित होता है कि जिन सीपीएसई का निजीकरण किया गया उनका प्रदर्शन प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले निजीकरण वाले वर्ष तक लगभग समान रहा। जबकि निजीकरण के बाद उनके प्रदर्शन में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले उल्लेखनीय सुधार हुआ।' उदाहरण के लिए, जिन 11 कंपनियों का निजीकरण किया गया उनकी शुद्ध हैसियत निजीकरण से पहले 700 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर निजीकरण के बाद 2,992 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2016-17 और वर्ष 2018-19 के बीच विनिवेश से सरकार को प्राप्त कुल रकम में रणनीतिक बिक्री की हिस्सेदारी करीब 28 फीसदी रही। वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने विनिवेश के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। लेकिन सरकार अब तक महज करीब 18,000 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है।

उदारीकरण-2 के लिए योजनाएं

उदारीकरण

भारत की अर्थव्यवस्था में नई निर्माण कंपनियों को तेजी से जोड़ने की जरूरत, नई कंपनियों की मदद से सुधारों की रफ्तार आगे बढ़ाए जाने पर जोर

अभिषेक वाघमारे
नई दिल्ली, 31 जनवरी

आर्थिक उदारीकरण के लगभग 30 साल बाद, एक औपचारिक दस्तावेज पेश किया गया है जिसमें न सिर्फ निजी क्षेत्र के योगदान को सराहा गया है बल्कि स्पष्ट रूप से यह सुझाव भी दिया गया है कि सरकार को पूंजीवाद को नए स्वरूप में अपनाना चाहिए।

एडम स्मिथ (जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है) से प्रेरणा लेते हुए आर्थिक समीक्षा में तेज आर्थिक वृद्धि के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए मुक्त बाजार की नई शक्तियों को जरिया बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक भरोसेमंद संस्थान की जिम्मेदारियां निभानी होंगी कि लालच स्वार्थी हितों को बढ़ावा न दे।

समीक्षा में सीईए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने लिखा है, '5 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा काफी हद तक बाजार की अदृश्य ताकतों को मजबूत बनाए जाने के साथ साथ उस भरोसे पर निर्भर है जिससे बाजारों को मदद मिल सके।'

बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि सुब्रमण्यन ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रतता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र किया है, जिसमें मोदी ने कहा था कि संपत्ति निर्माताओं को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए समीक्षा में उस संदेह को दूर करने की कोशिश की गई जो बाजार अर्थव्यवस्था से प्राप्त होने वाले लाभ से जुड़ा हुआ है।

- **इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों ने कोयले में 5 प्रतिशत की तुलना में 7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है**
- **सड़क क्षेत्र और रेलवे के बीच तुलनात्मक रूप से सड़क क्षेत्र में तेज वृद्धि का जिक्र किया गया है**
- **रेल क्षेत्र में यात्रियों की संख्या लंबे समय से घट रही है लेकिन उदारीकरण को बढ़ाने का सुझाव**
- **एक जिले में नई कंपनियों की संख्या 10 फीसदी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में 1.8 फीसदी की वृद्धि होगी**

प्रमुख और परिवहन क्षेत्रों पर आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए समीक्षा में कहा गया है कि इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों (जो निजी हाथों में हैं) ने कोयले (जो सरकार के अधीन बना हुआ है) में 5 प्रतिशत की तुलना में 7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। इसमें सड़क क्षेत्र और रेलवे के बीच भी तुलना की गई है और तुलनात्मक रूप से सड़क क्षेत्र में तेज वृद्धि का जिक्र किया गया है। वहीं रेल क्षेत्र में यात्रियों की संख्या लंबे समय से घट रही है। लेकिन ढांचागत उदारीकरण सुधारों के लिए राह प्रशस्त करते हुए समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि इन सुधारों को नई कंपनियों के गठन को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए, समीक्षा में नई कंपनियों के लिए अनुकूल परिवेश मुहैया कराए जाने और उनके तथा पुरानी कंपनियों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

सरकार कुछ खास क्षेत्रों की नई निर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर घटाकर इस दिशा में कदम पहले ही उठा चुकी है। निर्माण कंपनियों के लिए यह कर घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है।

समीक्षा में कहा गया है कि एक जिले में नई कंपनियों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में 1.8 प्रतिशत का इजाफा होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि सरकार को आंकड़ों पर विचार कर निर्माण क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

इसमें कहा गया है, 'चूंकि निर्माण क्षेत्र में अधिकतम नौकरियां पैदा करने की संभावना है, इसलिए राज्यों को व्यवसाय करने की प्रक्रिया आसान बनाने और तेजी से रोजगार सृजन के लिए श्रम कानूनों को लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।'

इस क्षेत्र को मौजूदा आर्थिक मंदी के प्रभाव से जूझना पड़ रहा है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार निर्माण क्षेत्र में मूल्य वृद्धि वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में प्रभावित हुई और पूरे वित्त वर्ष में वृद्धि 2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

नेटवर्क उत्पादों के निर्यात के लिए चीनी मॉडल का सुझाव

निर्यात

कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल उपकरण एवं दूरसंचार उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की जरूरत

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 31 जनवरी

आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि भारत को चीन की व्यापार रणनीति से सबक लेते हुए उत्पादों को विशेषीकृत बनाने और नेटवर्क उत्पादों की चुनिंदा श्रेणी जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल उपकरण एवं दूरसंचार उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की जरूरत है। इससे वर्तमान में खस्ताहाल निर्यात क्षेत्र को बल मिलेगा।

समीक्षा में यह भी कहा गया है कि सरकार को अपनी मेक इन इंडिया नीति के तहत 'विश्व के लिए भारत में असेंबलिंग' पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नेटवर्क उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने से भारत 2025 तक निर्यात बाजार में अपनी हिस्सेदारी वैश्विक औसत का करीब 3.5 फीसदी और 2030 तक 6 तक बढ़ा सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान लघु अवधि में रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित होंगे। भारत ने घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देते हुए और तैयार माल पर शुल्क लगाते हुए चीन से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात पर लगाम लगाया है।

नेटवर्क उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने से 2025 तक अर्थव्यवस्था में 248 अरब डॉलर का अतिरिक्त मूल्य सृजन होगा

हालांकि सरकार ऐपल और सैमसंग जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों से संपर्क बढ़ाने में रफ्तार दिखा सकती है क्योंकि आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि अधिकतर नेटवर्क उत्पादों के लिए उत्पादन प्रक्रिया को प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के दायरे में नियंत्रित करती हैं।

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने अपने पूर्ववर्ती अरविंद सुब्रमण्यन के उस विचार को आगे बढ़ाया है जिसके तहत कहा गया है कि अत्यधिक श्रम वाले विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने से उत्पादकता में सुधार, रोजगार सृजन और निर्यात जैसे कई फायदे एक साथ होते हैं। समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि नेटवर्क उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने से 2025 तक अर्थव्यवस्था में 248 अरब डॉलर का अतिरिक्त मूल्य सृजन होगा। नीति निर्माताओं के लिए अच्छी बात यह भी हो सकती है कि समीक्षा में कहा गया है कि नेटवर्क उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने से 2025 तक रोजगार के करीब 4 करोड़ अवसर सृजित होंगे जो बाद में बढ़कर 2030 तक करीब 8 करोड़ तक पहुंच सकता है।

अत्यधिक श्रम वाले अन्य क्षेत्रों जैसे कपड़ा और चमड़ा जैसे क्षेत्रों में सरकार ने ढांचागत सुधार करने के संकेत दिए हैं। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि प्रमुख बाजारों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लक्षित योजना से वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय सुधार होगा।

कारोबारी सुगमता में सुधार हो

कारोबारी सुगमता

निर्यात में मजबूती के लिहाज से सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 31 जनवरी

वैश्विक स्तर पर कारोबारी सुगमता की रैंकिंग में भारत की स्थिति भले ही सुधरी हो, लेकिन आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि जमीनी स्तर के कई मसले अभी भी बने हुए हैं। इस मामले में कहा जा सकता है कि निर्यात को आसान बाने की खातिर कस्टम की प्रक्रियाओं को नरम बनाने पर लगातार ध्यान दिए जाने के बावजूद निर्यात में मजबूती के लिहाज से यह बड़ा अवरोधक बना हुआ है।

अभी निर्यात और आयात में बॉर्डर पर व दस्तावेजी अनुपालन में क्रमश: 60-68 व 88-82 घंटे लगते हैं। दूसरी ओर, कस्टम से जुड़ी कार्यवाही में सबसे कम वक्त इटली में लगता है, जहां आयात-निर्यात के लिए ऐसी प्रक्रियाएं एक-एक घंटे में पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त इटली में जहां अनुपालन की लागत शून्य है, वहीं भारत में निर्यातकों को निर्यात के लिए अनुपालन पर 260-281 डॉलर खर्च करना होता है। इसके अतिरिक्त समय के कारण होने वाली देरी और प्रक्रियागत अकुशलता कारोबार की लागत को और बढ़ा देता है।

समय के कारण होने वाली देरी और प्रक्रियागत अकुशलता कारोबार की लागत को और बढ़ा देता है

समीक्षा में निर्यात के महत्वपूर्ण क्षेत्र अपैरल के कंसाइनमेंट में लगने वाले मानक समय के बारे में जानकारी दी गई है, जिमें हाल के वर्षों में कमी आई है और यह बांग्लादेश व वियतनाम से सस्ते विकल्पों के जरिए हुआ है।

साल 2018-19 में निर्यात 16 अरब डॉलर रहा, जो सालाना आधार पर 0.7 फीसदी घटा। निश्चित अवधि के रोजगार के लिए प्रमुख नियामकीय व श्रम कानून में बदलाव तीन साल बाद भारत के सबसे बड़े बाजार अमेरिका को अपैरल का निर्यात स्थिर बना हुआ है।

सस्ते भोजन ने संवारी आम आदमी की जिंदगी

खाद्य

पीडीएस वाले अनाज के दाम बढ़ाने और इसका कवरेज सीमित कर सब्सिडी पर काबू पाने की वकालत

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 31 जनवरी

खाद्य पदार्थों के दाम गिरने से 2016-17 से लाखों की संख्या में किसानों में देशव्यापी आक्रोश है, क्या इससे किसी को लाभ हुआ है? हां, अगर आप शाकाहारी खाना खाते हैं तो आपके परिवार को सालाना करीब 10,887 रुपये और अगर मांसाहारी खाना खाते हैं तो 11,787 रुपये फायदा हुआ है।

2019-20 की आर्थिक समीक्षा में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, 'थालीनॉमिक्स'। इसमें यह समझने की कवायद की गई है कि कम महंगाई दर की वजह से आम आदमी के खाने की थाली पर क्या असर पड़ा है और क्या उसकी स्थिति इस दौरान बेहतर या खराब हुई है। इसमें पाया गया है कि महंगाई कम होने से एक औसत आम आदमी के लिए 2006-07 से 2019-20 के बीच शाकाहारी थाली की वहनीयता 29 प्रतिशत जबकि मांसाहारी थाली की 18 प्रतिशत बढ़ी है। समीक्षा में पाया गया है, 'हमने पाया है कि महंगाई के हिसाब से थाली की कीमत और उसके सभी सामान के दाम में समीक्षावधि के दौरान गिरावट आई है। मजदूर के प्रतिदिन के भुगतान के हिसाब से थाली सस्ती रही है, जिससे आम आदमी के कल्याण होने के संकेत मिलते हैं।' थालीनॉमिक्स कुछ बिग मैक इंडेक्स के भारतीय संस्करण जैसा है, जिसमें पाया गया है कि 2019-20 के पहले 7 महीने के दौरान आम आदमी के लिए थाली पिछले 3 साल की तुलना में कम वहनीय हुई है। वहनीयता सूचकांक औद्योगिक कामगार की औसत सालाना कमाई का इस्तेमाल करके बनाया गया है।

थाली की सामग्री

शाकाहारी	मात्रा	मांसाहारी	मात्रा
अनाज	300 ग्राम	अनाज	300 ग्राम
सब्जियां	150 ग्राम	सब्जियां	150 ग्राम
दालें	60 ग्राम	मांसाहार	60 ग्राम

प्रतिदिन दो बार भोजन करने वाले पांच लोगों के परिवार की राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	शाकाहार थाली	मांसाहार थाली
2016-17	0.40 प्रतिशत	4.30 प्रतिशत
2017-18	6.50 प्रतिशत	5.60 प्रतिशत
2018-19	10 प्रतिशत	9.70 प्रतिशत
2019-20*	9 प्रतिशत	8.70 प्रतिशत

*अप्रैल-अक्टूबर 2019 की अवधि के दामों के आधार पर
स्रोत : आर्थिक समीक्षा - 2019-20

समीक्षा में कल्पना की गई है कि 5 लोगों का एक औसत परिवार एक दिन में दो थाली खाता है, जिसमें 300 ग्राम मोटे अनाज, 150 ग्राम सब्जियां, 60 ग्राम दाल होती है। मांसाहारी थाली में सभी चीजें समान होती हैं, जिसमें 60 ग्राम दाल की जगह इतनी ही मात्रा में मांसाहारी खाना जैसे अंडा, मांस या मछली शामिल कर लिया जाता है।

ईंधन में सूचकांक में रसोई गैस की कीमतें और जलावन लकड़ी के दाम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं। समीक्षा में दावा किया गया है कि 2015-16 को ऐसा साल माना जा सकता है, जब थाली के दाम में बदलाव हुआ, क्योंकि उस समय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने हेतु तमाम सुधार किए गए और कृषि बाजारों को बेहतर करने, पारदर्शी मूल्य की तलाश के लिए कदम उठाए गए।

दिलचस्प है कि जहां एक तरफ पिछले कुछ साल के दौरान खाद्य के दाम गिरने से आम आदमी को होने वाले लाभ गिनाए गए हैं वहीं समीक्षा में मोटे अनाज के दाम बढ़ाने की वकालत की गई है, जिसका वितरण राशन की दुकानों के माध्यम से होता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम के तहत आने वाले लोगों की संख्या कम की जानी चाहिए, जिससे कि सब्सिडी पर लगाम लगाई जा सके।

बढ़ती जरूरत के आगे बौने हैं देसी बैंक

बैंक

पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी बैंकों का प्रभावी होना जरूरी

भाषा
नई दिल्ली, 31 जनवरी

शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2019-20 में देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं के आगे भारतीय बैंकों के छोटे आकार (बौनेपन) पर चिंता जाहिर की गई है। समीक्षा में कहा गया कि देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकारी बैंकों को प्रभावी होना चाहिए तथा ऋण कम करने के बजाय उन्हें आर्थिक वृद्धि में सहायक होना चाहिए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी 2014 तक गरीब आबादी का बड़ा हिस्सा बैंकिंग सेवाओं से वंचित बना रहा। समीक्षा में सचेत किया गया कि सरकारी बैंकों की अक्षमता के कारण विशेष अवसरों को भुना सकने की देश की क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

समीक्षा के अनुसार, भारतीय बैंकिंग में बाजार हिस्सेदारी का करीब 70 फीसदी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पास है। यदि सरकारी बैंक भी भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में बड़े हों तो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ही नहीं कम से कम छह भारतीय सरकारी बैंक होने चाहिए। समीक्षा में बैंकिंग की सभी क्रिया प्रणालियों में वित्तीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने तथा कर्मचारियों को शेयर में हिस्सेदारी देने का सुझाव दिया गया है। समीक्षा में ऋण संबंधी निर्णयों विशेषकर बड़े कर्जदाताओं के मामले में वृहद सूचनाओं, कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करने के लिए जीएसटी नेटवर्क जैसा निकाय गठित करने का भी सुझाव दिया गया। इसमें सरकारी बैंकों के नेटवर्क पीएसबीएन को कर्जदारों की विस्तृत निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की जरूरत पर बल दिया गया है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि सरकारी बैंकों में केंद्र सरकार द्वारा पूंजी डालने के माध्यम से करदाताओं की लगभग 4,30,000 करोड़ रुपये की धनराशि निवेश की गई। वर्ष 2019 में बैंकों में करदाताओं को निवेश पर औसतन 23 फीसदी का घाटा हुआ।

दिवालिया संहिता से मामले का समाधान औसतन 340 दिनों में ऋणशोधन कानून के तहत मामलों के समाधान में अब 340 दिन का समय लग रहा है जबकि पूर्व व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया में करीब 4.3 साल का समय लगता था। वर्ष 2016 में अस्तित्व में आया ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) कानून दबाव वाली संपत्ति के लिए बाजार आधारित और सबयबद्ध समाधान व्यवस्था उपलब्ध कराता है।

समीक्षा में यह भी कहा गया है कि आईबीसी के तहत मामलों के समाधान की संख्या पूर्व प्रक्रियाओं के मुकाबले कहीं अधिक है। इसमें यह भी कहा गया है कि फंसी राशि के प्रतिशत के रूप में 2017-18 और 2018-19 में जो राशि वसूली गई, वह लोक अदालत और कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) समेत अन्य के मुकाबले कहीं अधिक है।

दाम घटाने से बिक सकेंगे फ्लैट

रियल्टी | डेवलपरों का कहना है कि यह सुझाव अव्यावहारिक है, खपत और नकदी बढ़ाने के लिए नीति का गठन जरूरी

अर्णव दत्ता, समरीन अहमद और राघवेंद्र कामत
नई दिल्ली/बेंगलूरु/मुंबई, 31 जनवरी

अर्थव्यवस्था की वृद्धि में आई गिरावट के लिए रियल एस्टेट की अहम क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुए 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि रियल्टर्स को कुछ घाटा उठाकर विरासत में मिली समस्याओं को हल करने की जरूरत है। अगर डेवलपर कीमतें कम करते हैं तो मकानों की बिक्री बढ़ेगी और उन्हें अपने कर्जदाताओं के बही खाते साफ करने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक एक समय में उफान पर रहा हाउसिंग क्षेत्र बगैर बिके मकानों के संकट से जूझ रहा है, जबकि कीमतें अधिक बनी हुई हैं। समीक्षा के मुताबिक, 'परियोजनाओं की डिलिवरी में देरी और अटकी हुई परियोजनाओं की वजह से कई साल से बगैर बिके मकान पड़े हुए हैं' जिसकी वजह से 2011 के बाद से ही संकट की स्थिति बन गई है। इसमें कहा गया है कि आवास, अन्य इमारतों और ढांचों में निवेश 2011-12 से 2017-18 के दौरान गिरा है, जिससे पता चलता है कि प्रति परिवार मकानों की खरीद की वृद्धि सुस्त रही है।

अप्रैल-जून 2015-16 के बाद से कीमतों में वृद्धि की तरह बहुत तेजी से गिरी है और उसके बाद से स्थिरता बनी हुई है, लेकिन सालाना बिक्री के हिसाब से बगैर बिके मकान का स्तर बढ़ा है। इसमें कहा गया है, 'दिसंबर 2018 के अंत तक प्रमुख 8 शहरों में 7.77 लाख करोड़ रुपये के करीब 9,43,000 फ्लैट विभिन्न स्तर पर अटके हुए हैं।'

इस क्षेत्र को उबारने के लिए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि, 'मौजूदा बगैर बिके आवास को बेचा जा सकता है और बैंक व गैर बैंकिंग कर्जदाताओं की बैलेंस शीट साफ की जा सकती है, अगर रियल एस्टेट डेवलपर थोड़ा घाटा उठाने को इच्छुक हों और मकान के दाम गिरने दें।'

समीक्षा में मकानों के दाम घटाकर बिक्री बढ़ाने का सुझाव दिया गया है

बहरहाल इस सुझाव से रियल एस्टेट डेवलपर और उद्योग के विशेषज्ञ प्रभावित नहीं हैं। उनका कहना है कि ऐसे समय में जब डेवलपर कीमतें तय करने की स्थिति में न होने के कारण दीवालिया हो रहे हैं, मुनाफे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कीमतों में कटौती का सुझाव व्यावहारिक नहीं है।

हीरानंदानी समूह के प्रबंधन निदेशक और एसोचेम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि कीमतों में कटौती के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, 'कुछ परियोजनाओं और कुछ इलाकों में कीमतों में कटौती हो सकती है। लेकिन हर जगह डेवलपर कीमतों में कमी नहीं कर सकते।' रियल एस्टेट दिग्गज पूर्वांकरा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आशीष पूर्वांकरा ने कहा, 'सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में बिक्री में बढ़ोतरी की कई वजहें होती हैं, जिनमें ग्राहकों की धारणा से लेकर आर्थिक परिदृश्य तक शामिल होता है। तमाम डेवलपर ग्राहकों को कई तरह के प्रोत्साहन देते रहते हैं, लेकिन कीमतों में कमी करना टिकाऊ योजना नहीं है।'

उनके मुताबिक कई कारक एक साथ काम करें तभी बिक्री को गति दी जा सकती है। उन्होंने कहा, 'कर्ज के क्षेत्र में सुधार, आकर्षक और आसान आवास ऋण के पैकेज के साथ सबसे अहम उपभोक्ताओं की मजबूत धारणा है, जो वित्तीय भरोसे से ही आ सकती है। खपत को नीतिगत स्तर पर बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है।'एक प्रमुख डेवलपर के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि शहरी इलाकों में जमीन की कमी, निर्माण लागत में बढ़ोतरी और ज्यादा शुल्क व कर प्रमुख बाधाएं हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट क्षेत्र कीमतों में कटौती करने में सक्षम नहीं है। डेवलपर इस समय नकदी के संकट से जूझ रहे हैं, जिसके समाधान की जरूरत है।

आम आदमी चुकाता है इरादतन चूक की कीमत

चूक | 2018 में ऐसे चूककर्ताओं पर बैंकों का करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये बकाया था

जश कृपलानी
मुंबई, 31 जनवरी

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इरादतन चूक करने वालों की तरफ से की गई रकम की हेराफेरी को अगर वापस अर्थव्यवस्था में लाया जाए तो यह रकम सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के बजट आवंटन के लिए पर्याप्त हो सकता है। साथ ही समीक्षा में यह भी कहा गया है कि प्रवर्तकों की तरफ से संबंधित पक्षकार के लेनदेन का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था से रकम बाहर भेजने के लिए हुआ।

> सिर्फ 40 फीसदी इरादतन चूककर्ता संबंधित पक्षकार के लेनदेन का खुलासा करते हैं

समीक्षा में कहा गया है कि इरादतन चूककर्ताओं को दी गई उधारी का हर रुपया संपत्ति का क्षरण करता है और मौजूदा कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से अब तक ऐसे चूककर्ताओं की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताता है।

समीक्षा के मुताबिक, और अमीर बनने को इच्छुक धनाढ्य कारोबारी इरादतन चूक का इस्तेमाल गरीबों से संपत्ति दूर करने के लिए करते हैं।

साल 2018 तक इरादतन चूककर्ताओं पर लेनदारों का करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये बकाया था। भारत में ऐसे इरादतन चूककर्ता अत्यधिक गिरवी और संबंधित पक्षकार के लेनदेन को छुपाने वाला अनूठा तरीका अपनाते हैं।

संबंधित पक्षकार के लेनदेन के तहत मोटे तौर पर बड़ा कर्ज, अन्य संबंधित पक्षकारों को सामान की बिक्री या खरीद होता है, जिसके बारे में समीक्षा में कहा गया है कि इरादतन चूककर्ताओं यही हथकंडा अपनाते हैं।

साथ ही ऐसे प्रवर्तकों के बीच अपारदर्शिता और नियामकीय अनुपालन का ज्यादा अभाव देखा जाता है। सिर्फ 40 फीसदी इरादतन चूककर्ता संबंधित पक्षकार के लेनदेन का खुलासा करते हैं, जो हालांकि कानूनन अनिवार्य है। गैर-इरादतन चूककर्ता और दबाव वाले चूककर्ताओं की तरफ से अनुपालन की दर 60 फीसदी है।

समीक्षा के मुताबिक, चूक करने वाली फर्मों के प्रवर्तक अपनी हिस्सेदारी का औसतन 50 फीसदी लेनदारों के पास गिरवी रखते हैं। वित्तीय दबाव का सामना कर रहे प्रवर्तक अपनी शेयरधारिता का करीब 30 फीसदी गिरवी रखते हैं जबकि चूक न करने वाले 11 फीसदी।

एनआईपी में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी 30 प्रतिशत!

इन्फ्रास्ट्रक्चर | पिछले साल दिसंबर में वित्त मंत्री ने 19.63 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की थी

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 31 जनवरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा कि वर्ष 2025 तक 'नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन' (एनआईपी) में निजी क्षेत्र की निवेश भागीदारी 30 प्रतिशत पर पहुंच सकती है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश में वृद्धि जरूरी है। वर्ष 2024-25 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर इन वर्षों के दौरान लगभग 1.4 लाख करोड़ डॉलर का खर्च किए जाने की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा कि सालाना इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ाना बेहद महत्त्वपूर्ण होगा जिससे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक न बने। उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्टक्चर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि परियोजनाएं पूरी तरह से तैयार और शुरू की जाएं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ेगी भागीदारी

31 दिसंबर को सीतारमण ने 19.63 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की थी। एनआईपी के तहत, परियोजनाओं के वित्त पोषण में केंद्र सरकार (39 प्रतिशत) और राज्य सरकार (39 प्रतिशत) की समान भागीदारी रहने के अनुमान है, जिसके बाद निजी क्षेत्र का 22 प्रतिशत योगदान रह सकता है।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिए एनआईपी तैयार किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में सितंबर 2019 में एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल गठित किया गया था।

एनआईपी से संपूर्ण रूप से तैयार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मदद मिलेगी जिससे रोजगार पैदा होंगे, रहन-सहन के स्तर में सुधार आएगा, और सभी को बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच हासिल होगी। एनआईपी के तहत अल्पावधि के साथ साथ संभावित जीडीपी वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचा विकास में आपूर्ति को भी सुगम बनाने पर जोर दिया गया है।

सड़क निर्माण की गति हुई मंद

सड़क निर्माण | 2019-20 की पहली छमाही में रोजाना सड़क निर्माण की दर 2018-19 के मुकाबले हुई आधी

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 31 जनवरी

विकास के लिए अच्छी सड़कों एवं परिवहन के महत्त्व पर जोर देते हुए आर्थिक समीक्षा 2019-20 में बताया गया कि कुछ समय पहले सुधरा प्रतिदिन सड़क निर्माण आंकड़ा एक बार फिर घटकर चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में आधे से भी कम हो गया है।

वित्त वर्ष 2015-16 में प्रतिदिन 17 किलोमीटर सड़क निर्माण होता था जो साल 2018-19 में तेजी से बढ़कर 29.7 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच गया था। हालांकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान यह गति एक बार फिर मंद हो गई और इस वित्त वर्ष में सितंबर 2019 तक यह आंकड़ा 12.7 किलोमीटर प्रतिदिन रहा। जीवीए तथा यातायात में हिस्सेदारी के मामले में परिवहन क्षेत्र के योगदान में सड़क परिवहन की अहम भूमिका रहती है।

साल 2017-18 के दौरान जीवीए परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 4.77 प्रतिशत थी जिसमें सड़क परिवहन की सबसे अधिक 3.06 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। इसके बाद रेलवे की 0.75 प्रतिशत, हवाई यातायात की 0.15 प्रतिशत और जल मार्ग की 0.06 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।

इसी तरह, राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान देश के माल ढुलाई एवं यात्री परिवहन में सड़क यातायात की हिस्सेदारी क्रमशः 69 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत थी।

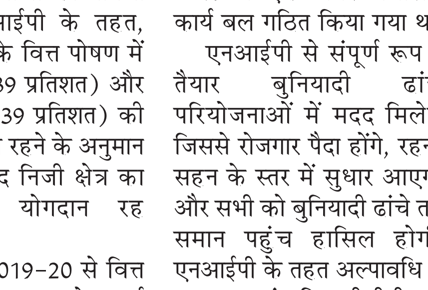

धीमी रही सड़क निर्माण की गति

देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने आर्थिक समीक्षा में कहा कि अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि के लिए अच्छे सड़क मार्ग का होना बहुत जरूरी है। सड़क को अलग करके नहीं देखा जा सकता और इसे हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह और दूसरे जरूरी संसाधनों के साथ मिलाकर तैयार की जा रही बहुआयामी परिवहन प्रणाली का ही हिस्सा माना जाना चाहिए।

31 मार्च 2018 तक भारत में करीब 59.64 लाख किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क मौजूद था। 01 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1.32 लाख किलोमीटर थी।

विदेशी निवेशक सतर्क

दलाल पथ | इस हफ्ते एफपीआई ने 6,000 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, वीआईएक्स में आई तेजी, ट्रेडरों को बाजार में उतार-चढ़ाव की आशंका

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 31 जनवरी

भारतीय बाजारों को आगे ले जाने में अहम विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने आम बजट से पहले अपना निवेश हल्का किया है। बजट शनिवार को पेश किया जाएगा। पिछले पांच कारोबारी सत्र में एफपीआई ने करीब 6,000 करोड़ रुपये की बिकवाली की है।

इस बिकवाली की एक अहम वजह कोरोनावायरस के प्रसार के कारण पैदा हुई जोखिम हो सकती है। हालांकि बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि समझदार निवेशकों की तरफ से बजट से पहले अपनी निवेश निकासी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्रवार को एफपीआई ने 4,179 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जो दो साल से ज्यादा अवधि में एक दिन की सबसे बड़ी बिकवाली है।

बाजार के उतारचढ़ाव की माप करने वाला इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स हफ्ते के दौरान 12 फीसदी उछल गया, जो संकेत देता है कि बजट के कारण बाजार में बड़ा परिचालन देखने को मिल सकता है। शनिवार को इक्विटी बाजार खुले रहेंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रेडरों ने खुद को उतारचढ़ाव वाले कारोबार के लिए तैयार कर लिया है।

विगत के आंकड़ों को देखें तो बेंचमार्क सेंसेक्स में भारी उतारचढ़ाव रहा है और बजट सत्र के आखिर में यह गिरकर बंद हुआ है। पिछले 15 बजट के दिन सेंसेक्स में औसतन 3 फीसदी का उतारचढ़ाव देखा गया है और इनमें से 10 कारोबारी सत्र में यह गिरकर बंद हुआ है।

बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि सरकार को राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण और वृद्धि को बहाल करने के लिए कदमों के ऐलान के बीच सही संतुलन बिठाना होगा और यह बाजार पर असर डालेगा। बीएनपी पारिबा के इक्विटी रिसर्च प्रमुख अभिराम एलेश्वरपू ने कहा, बाजार के लिहाज से बजट हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है। यह साल इसलिए खास है क्योंकि यह निवेशकों को बताएगा कि सरकार इस मंदी के बारे में क्या सोच रही है।

उन्होंने कहा, राजकोषीय घाटा अहम होता है। सरकार शायद राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को

बजट से पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हुए सतर्क, बिकवाली पर दिया जोर

उस स्थिति में शायद बरकरार रखने के बारे में सोच रही होगी कि उसे खर्च में कटौती की दरकार है क्योंकि राजस्व संग्रह अनुमान से कम रहा है। यह राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा, लेकिन मंदी को लंबा खींच देगा। अन्य विकल्प खर्च में कटौती नहीं करना है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से चूक जाएंगे, लेकिन यह उपभोक्ता के दबाव को कम करने का समाधान होगा।

मॉर्गन स्टैनली के इक्विटी रिसर्च प्रमुख रिधम देसाई ने कहा कि विभिन्न वर्षों में बाजार पर बजट का असर घटा है। हालांकि बाजार के लिहाज से यह अहम घटनाक्रम बना हुआ है। उन्होंने कहा, बाजार पर बजट का असर गिरावट के तौर पर दिखा है, इसके बावजूद बाजार के प्रतिभागियों को उतारचढ़ाव पर नजर रखने की दरकार है।

देसाई के मुताबिक, बुनियादी ढांचा व किसानों पर सरकार की खर्च की योजना और प्रत्यक्ष कर में बदलाव (लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर समेत) आदि कुछ ऐसी चीजें हैं, जो निवेशकों की धारणा को प्रभावित करेंगी। कुछ निवेशकों को उम्मीद है कि सरकार लाभांश वितरण कर, पुनर्खरीद कर और एलटीसीजी आदि में राहत देगी।

बीएस सूडोकू 3653

2				3				
		6		5	7		2	
4	5				2			3
		1	5		6		3	
	8		3		9	7		
1			7				5	8
	6		4	1		9		
				2				6

परिणाम संख्या 3652

7	2	5	3	4	1	6	9	8
4	9	6	5	8	7	1	3	2
8	3	1	2	9	6	4	5	7
6	1	8	9	3	5	2	7	4
5	4	9	7	6	2	8	1	3
3	7	2	4	1	8	9	6	5
2	6	3	8	7	9	5	4	1
9	5	4	1	2	3	7	8	6
1	8	7	6	5	4	3	2	9

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम
★★★☆☆

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 297

सलाहकार बनाम कर्ता

भारत में कोई भी यह जानकर चकित ही हो सकता है कि चीन ने वायरस से जूझ रहे वुहान प्रांत में 10 दिन से भी कम अवधि में कुल 2,300 बिस्तरों वाले दो अस्पताल बना दिए। यह कैसे संभव हुआ? उत्तर यह है कि एक अस्पताल तो पहले से ही बन रहा था जिसे मई में शुरू होना था। उसके निर्माण की समय सीमा को घटा कर मात्र 48 घंटे कर दिया गया। दूसरा उस अस्पताल का अनुकरण करके खोला गया जो सन 2003 में पेइचिंग में सार्स की महामारी से निपटने के लिए सप्ताह भर में खोला गया था। परंतु सवाल फिर भी बरकरार है। क्या जमीन अधिग्रहण में कोई समस्या नहीं आई? नहीं, क्योंकि अस्पताल का निर्माण पुनर्विकसित की जा रही एक जगह के पास किया गया जहां बगीचा था। क्या निर्माण कार्य की बोली तथा विशेष चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए बोली आमंत्रित करने में समय नहीं लगा? क्या बोलीकर्ता छांटने और सबसे कम पैसे वाली बोली लगाने वाले के चयन के लिए समिति नहीं बनानी पड़ी? ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि अस्पताल बनाने में सरकारी कंपनियां लगी हैं। वह कौन सी निर्माण तकनीक है जो इतने कम समय में नई इमारत तैयार कर सकती है? जाहिर है पूर्वनिर्मित ढांचे। इसके बावजूद ये अस्पताल दुनिया भर में सुर्खियों में हैं।

ऐसे में अगली आर्थिक समीक्षा के लिए अच्छा होगा कि वह न केवल अर्थशास्त्र में 'क्या' और 'क्यों' जैसे सवालों से जूझे बल्कि 'कैसे' का भी जवाब तलाशे। असंभव को संभव कैसे किया जाता है, यह समझने का इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। भारत बजट और प्रक्रियाओं से जूझता रहता है। अभी भी यहां भ्रष्टाचार इतनी बड़ी समस्या तो है ही कि वह किसी परियोजना को बेपटरी कर सके। चीन में भी भ्रष्टाचार है लेकिन 10,000 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय वाली कोई और अर्थव्यवस्था 6 फीसदी या उसके आसपास की दर से विकसित नहीं हो रही।

चीन ऐसा कैसे करता है जबकि केजरीवाल सरकार दिल्ली में पांच साल में बमुश्किल 450 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक खोल सकी जबकि उसने 1,000 क्लीनिक खोलने का वादा किया था। ताजा उपलब्ध रेलवे वार्षिकी में कहा गया है कि बीते दो वर्ष में हर वर्ष रेलवे 1.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश बजट में से केवल दो तिहाई ही खर्च कर पाया। काम करने में ऐसी नाकामी के बीच समीक्षा वृद्धि और रोजगार के लिए निर्यात की महत्ता, बाजार में सरकार के हस्तक्षेप से होने वाले नुकसान और निजीकरण के जरिये परिसंपत्ति निर्माण जैसी बहस पर कोई भी आपा खो सकता है। निश्चित तौर पर हमें ये सबक बहुत पहले लेने थे।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

इसके बहाने भी मौजूद हैं। चीन में अधिनायकवादी शासन है जहां आप भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अदालत नहीं जा सकते या ठेकेदार नहीं चुन सकते। वहां का शीर्ष से नीचे का निर्णय संबंधी ढांचा बाधाओं को दूर करने का काम करता है और वहां पैसे की कोई बाधा नहीं होती। इसके बावजूद आपको हैरानी होती है कि शांघाई का इकलौता शिपयार्ड देश के समूचे युद्धपोतों के बेड़े के बराबर निर्माण कार्य करता है। बल्कि इसके साथ वह विमान वाहक पोत, हॉवरक्राफ्ट और उपग्रहों का पता लगाने वाले पोत भी बनाता है। भारतीय नौसेना को अगर 20 साल में भी छह पुरानी तकनीक की पनडुब्बी मिल जाएं तो भी वह खुद को खुदकिस्मत मानेगी।

कोई हल है? हां, मेट्रो बनाने वाले ई श्रीधरन जैसे पुराने रेलवे इंजीनियर, डीवी कपूर और वी कृष्णमूर्ति जैसे सरकारी कंपनियों के निर्माता और एम एस स्वामीनाथन जैसे कृषि वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि कैसे मौका मिलने पर वे अंतर पैदा कर सकते हैं। भारतीय गैस प्राधिकरण के मुखिया के रूप में विनीत नैयर ने सन 1980 के दशक में एक बड़ी गैस पाइपलाइन तैयार की थी। स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत के प्रभारी अधिकारियों और इंदौर में स्वच्छता लाने वाले अधिकारी भले चीन का मुकाबला न कर पाएं लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शायद हमें उनके जैसे अन्य अधिकारियों को चिह्नित करना होगा और अवसर देना होगा।

भारत में अच्छी सलाह देने वालों की कमी कभी नहीं रही। समीक्षा का यह कहना सही हो सकता है कि भारत की ताजा वृद्धि दर अतिरंजित नहीं है और अगले वर्ष 6-6.5 फीसदी की दर हासिल हो सकती है। परंतु यह मानना गलत होगा कि मोदी सरकार अपने भारी जनादेश का इस्तेमाल कुछ गंभीर सुधार अपनाने में करेगी। यदि वित्त मंत्री सबको चौंकाती नहीं तो यह तय है कि सरकार की प्राथमिकता कुछ और है। वह देश के शक्तिशाली गृहमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है।

विनय सिन्हा

क्या उलट रहा है दशक पुराना मंदी का चक्र?

आर्थिक समीक्षा में मंदी के कारण और उसके संभावित निवारण को लेकर कुछ दिलचस्प तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इन पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं **अभीक बरुआ**

लंबी आर्थिक मंदी के दौर में लिखी गई आर्थिक समीक्षा का सबसे बेहतर आकलन इस आधार पर हो सकता है कि वह दो सवालों का जवाब देने में किस हद तक सक्षम है। पहला, क्या सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक समीक्षा के प्रमुख लेखक इस बात का उचित विश्लेषण प्रस्तुत कर पाते हैं कि हालात इतने संकटपूर्ण क्यों हुए? दूसरा, क्या उनके पास इस संकट को हल करने के उपाय हैं या कम से कम ऐसे उपाय जो अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट को थाम सकें?

मेरा मानना है कि आर्थिक समीक्षा मौजूदा आर्थिक मंदी को समझने में सफल रही है। इसमें नई अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है जो ढांचागत बनाम चक्रीय मंदी के पारंपरिक वर्गीकरण से परे है। इस सिलसिले में यह दावा करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2011-12 से ही वृद्धि में धीमेपन के प्रभाव में है। इसके मुताबिक मंदी की जड़ें सन 2000 के दशक के ऋण के बुलबुले में छिपी हैं जिसके कारण खपत और वृद्धि में अचानक तेजी आई थी। जब यह बुलबुला फूटा तो कंपनियां या तो दिवालिया हो गईं या इसका अनुमान होने पर उन्होंने अपना ऋण चुकाने की आपाधापी दिखाई। सन 2000 के दशक की ऋण आधारित तेजी मौजूदा दशक के साथ समापन की दिशा में बढ़ी।

कंपनियां क्षमता विस्तार के लिए नया ऋण लेने के बजाय पुराना कर्ज चुकाने में रुचि ले रही थीं। इससे निवेश प्रभावित हुआ। निवेश में गिरावट से जीडीपी वृद्धि प्रभावित होने लगी, इस धीमेपन ने खपत की मांग पर असर डाला। आर्थिक जगत का गणित कुछ ऐसा है कि मंदी का असर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक परिलक्षित होने में काफी वक्त लेता है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि निजी निवेश जीडीपी को 3-4 वर्ष के अंतराल पर प्रभावित करती है और जीडीपी वृद्धि का खपत पर प्रभाव 1-2 वर्ष के अंतर पर सामने आता है। इस हिसाब से देखें तो खपत में मंदी का सिलसिला 2017-18 में प्रभावी हुआ। धीमी वैश्विक वृद्धि और वित्तीय क्षेत्र पर बढ़े हुए जोखिम से ऐसी आर्थिक मंदी उत्पन्न होती है जिसने कुछ वर्ष से हमारी अर्थव्यवस्था को चपेट में लिया है।

क्या इसका अंत नजर आ रहा है? आर्थिक समीक्षा का यकीन है कि 2019-20 में आर्थिक चक्र निम्नतम स्तर छू चुका है। उसने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के 5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है लेकिन 2020-21 में इसके 6-6.5 फीसदी रहने की बात कही गई है। अन्य अनुमानों को देखें तो यह थोड़ा आशावादी लगता है लेकिन यह हकीकत से दूर कतई नहीं है क्योंकि इसका अर्थ है 10 से 10.5 फीसदी की नॉमिनल वृद्धि दर। आज पेश हो रहे आम बजट में ऐसा देखने को मिल सकता है।

इस वर्ष से अगले वर्ष के बीच जीडीपी में एक फीसदी की वृद्धि कैसे आएगी? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आर्थिक समीक्षा उस मौजूदा बहस का सहारा लेती है जिसमें यह सवाल है कि इस मोड़ पर राजकोषीय प्रोत्साहन अपनाना चाहिए या सुदृढ़ीकरण। यह प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति की बात करता है जिसके तहत या तो सरकार कर कटौती या फिर आय हस्तांतरण के जरिये लोगों को और अधिक पैसा दे या फिर खुद अधिक व्यय करे। इससे उन्हें परेशानी हो सकती है जिनका कहना है कि मंदी आ चुकी है लेकिन आर्थिक समीक्षा तीन वजहों से चिंता की बात नहीं मानती।

पहली बात, ऋण के पोर्टफोलियो में बाहरी कर्ज की हिस्सेदारी बहुत कम है और लगभग पूरी बाहरी उधारी आधिकारिक स्रोतों से होने के कारण ऐसी आशंका नहीं है कि उभरते बाजार का संकट उत्पन्न होगा। दूसरी बात अधिकांश सरकारी कर्ज तयशुदा ब्याज दरों पर लिया गया है इससे देश का ऋण, ब्याज दरों की अस्थिरता से बचा हुआ है। तीसरी बात, केंद्र सरकार के कर्ज का प्रोफाइल ऐसा है जो कर्ज के रोल ओवर का जोखिम कम करता है।

आर्थिक समीक्षा जहां मौजूदा मंदी के कारणों और हल को लेकर विश्वस्त नजर आती है वहीं परंतु वित्तीय क्षेत्र के कारोबार में जोखिम कम करने की बात करें तो वह बात करने की इच्छुक नहीं दिखती। संकट से जूझ रहे अचल संपत्ति और खतरनाक परिसंपत्ति का बोझ ढो रही आवास वित्त क्षेत्र की कंपनियों के लिए सीईए के पास इकलौती सलाह यही है कि वे इन्वेंटरी कम करने के लिए आवास कीमतें कम करें। वित्तीय तंत्र को जाम करने वाली खराब परिसंपत्तियों के लिए किसी राजकोषीय व्यवस्था का उल्लेख न करना निराश करता है। कुछ लोग कहेंगे कि यदि आज पेश होने वाले बजट में भी इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया तो आर्थिक सुधार में देरी होगी।

दिलचस्प बात है कि आर्थिक समीक्षा की तथाकथित थीम है 'एनेबल मार्केट्स, प्रमोट प्रो बिजनेस पॉलिसीज ऐंड स्ट्रेंथन ट्रस्ट इन इकनॉमी।' इसके अलावा समीक्षा के पहले भाग की शुरुआत नैतिक रूप से परिसंपत्ति तैयार करने से होती है और इसमें 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कारोबार और बाजार के अनुकूल नीतियां बनाने की बात शामिल हैं। बाजार और कीमतों में सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ तगड़ी दलीलों के साथ यह सरकार और उद्योग जगत के बीच नए सिरे से ताल्लुकात का प्रयास करती है। उद्योग जगत प्राय: यह शिकायत करता है कि उसे तवज्जो नहीं दी जाती। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सीईए उद्योग जगत को शांति प्रस्ताव दे रहे हैं या वह सरकार के अपने सहयोगियों को इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील करने का प्रयास कर रहे हैं।

आर्थिक समीक्षा पर कोई निर्णयात्मक टिप्पणी करना कठिन है। जहां तक मंदी को लेकर इसकी अवधारणा की बात है, यह दिलचस्प है। हो सकता है अधिकांश आर्थिक मॉडलों की तरह इसके अनुमान भी गलत साबित हों। बहरहाल यह इस लिहाज से विश्वसनीय और स्वतंत्र है कि इसमें मौजूदा आर्थिक स्थिति को नकारा नहीं गया है। न ही इसमें सरकार की आर्थिक नीतियों का बचाव किया गया है। अन्य आर्थिक समीक्षाओं की तरह इसके साथ दिक्कत यही है कि यह व्यापक दृष्टिकोण नहीं दर्शाती। भविष्य के अनुमान के लिए हमें बजट का इंतजार करना होगा।

कोरोनावायरस से निपटने के लिए दुनिया कितनी है तैयार

चिकित्सा विज्ञान

देवांग्शु दत्ता

चीन ने गत 31 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया था कि उसके हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में कुछ लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हुए हैं। इस वायरस के संक्रमण का पहला मामला चीन में 8 दिसंबर को सामने आया था। अब तक यह वायरस 9,800 से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है और इससे 200 से अधिक की मौत हो चुकी है। एक करोड़ से अधिक आबादी वाले वुहान और कुछ अन्य शहरों को अलग-थलग करने की कोशिशों के बावजूद इस घातक वायरस का प्रसार थम नहीं रहा है।

इसका प्रसार दुनिया के कई देशों में हो चुका है। यह भारत में भी दस्तक दे चुका है। वुहान यूनिवर्सिटी से लौटी केरल निवासी एक छात्रा को संक्रमित पाया गया है। चीन की करीब चार करोड़ आबादी नो-ट्रैवल जोन घोषित किए जा चुके इलाके में रहती है। चीन में कई उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। चीन से आने वाले यात्रियों को दो हफ्ते तक निषिद्ध रखने की बात ब्रिटेन ने की है और भारत भी इसी तरह का प्रतिबंध लगा चुका है।

यह जानवरों एवं पक्षियों से फैलने वाला वायरस है जो इंसानों को भी संक्रमित कर देता है। मसलन, चीन में ही दस्तक देने वाला सार्स वायरस भी चमगादड़ों एवं कस्तूरी बिलाव से इंसानों तक पहुंचा था। माना जाता है कि वुहान का नॉवेल कोरोनावायरस भी किसी जानवर या पक्षी से ही इंसान तक पहुंचा है और अब यह एक से दूसरे इंसान तक फैलता जा रहा है। जहां इस बीमारी में फ्लू से मिलते-जुलते लक्षण नजर आते हैं वहीं कई दिनों तक संक्रमण के बाद भी कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। संक्रामक बीमारियों का प्रसार कई कारणों पर निर्भर करता है जिनमें से एक बढ़िया ढांचागत आधार भी है। इक्कीसवीं सदी में संक्रमित लोग कुछ ही घंटों में दुनिया के दूसरे छोर पर जा सकते हैं। और चीन के पास बेहतरीन ढांचागत आधार होने से वहां से संक्रामक बीमारी के तीव्र प्रसार की आशंका और अधिक है। इसके पहले हम 2003 में भी सार्स के संक्रमण के समय इसे देख चुके हैं। चिकित्सा क्षेत्र के जानकार किसी बीमारी की संक्रामक क्षमता को बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर (आर0) की गणना से आंकते हैं।

आर0 का आशय इससे है कि कोई संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ या मृत होने के पहले औसतन कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? जिस बीमारी का आर0 अधिक होता है वह उतना ही अधिक संक्रामक मानी जाती है। अगर आर0 एक से कम है तो फिर वह बीमारी खुद-ब-खुद सिमट जाने वाली है और धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। अगर आर0 एक से अधिक है तो फिर संक्रमित व्यक्ति को अलग न रखने पर बीमारी फैलती जाएगी। आर0 संख्या में काफी भिन्नता भी हो सकती है। मसलन, इन्फ्लुएंजा का आर0 नंबर 2 से 3 होता है जबकि खसरा का आर0 12 से 18 तक होता है। सामान्य सर्दी-जुकाम जैसा बेहद संक्रामक वायरस भी घातक नहीं होता है लिहाजा उससे डरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इबोला जैसी उच्च घातक दर वाली एक संक्रामक बीमारी बेहद डरावनी होती है।

जहां तक कोरोना का सवाल है तो इसके आर0 नंबर और न ही इसकी मृत्यु दर के बारे में ही अधिक सटीक आंकड़े उपलब्ध हो पाए हैं। लेकिन शोधकर्ता प्रारंभिक अनुमान लगा रहे हैं। कई लेखकों की भागीदारी वाले दो शोध-पत्र सामने भी आ चुके हैं।

हॉन्गकॉन्ग की एक शोध टीम द्वारा प्रकाशित शोध-पत्र में कहा गया है, 'हमारा अनुमान है कि इस वायरस का माध्य आर0 2.24 से लेकर 3.58 के बीच है और मामले सामने आने की दर दोगुनी से आठ-गुनी है।' अगर आर0 नंबर को सबसे निचले स्तर 2.24 पर भी रखें तो इसका मतलब है कि यह बीमारी तेजी से फैलने वाली है।

वहीं ग्वांगतोंग प्रांत के बीमारी नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने अपने शोध-पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उसके लक्षण उजागर होने में 4.8 दिन लगते हैं। एक बार लक्षण सामने आने के बाद 2.9 दिन में मरीज को अलग रखने की नौबत आ जाती है जबकि सार्स वायरस के मामले में यह स्थिति 4.2 दिन में आती है। इसके मुताबिक 'महामारी फैलाने के लिहाज से सार्स की तुलना में नॉवेल कोरोना अधिक जोखिम वाला है। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर पर किए गए प्रयासों ने इस महामारी का खतरा काफी कम किया है। लेकिन इसका प्रसार रोकने के लिए अधिक सख्त नियंत्रण एवं रोकथाम संबंधी उपायों की जरूरत है।'

चीन के वैज्ञानिकों ने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को कोरोनावायरस से संबंधित जानकारियां देने में काफी तत्परता दिखाई है। चीन ने 10 जनवरी तक इस वायरस की जीनोम संरचना जारी कर दी थी। इससे फ्लू की तरह लक्षणों वाले मरीजों का फौरन परीक्षण कर कोरोना से संक्रमित होने के बारे में पता लगाया जा सकता है।

लेकिन जीनोम संरचना तैयार करना इस वायरस की वैक्सीन तैयार करने की दिशा में महज पहला कदम है। विभिन्न मरीजों से लिए गए नमूनों के आधार पर यह जीनोम तैयार हुआ है। वैसे शुरुआती दौर के मरीजों के जीनोम की तुलना बाद में मिले जीनोम से कर इस वायरस में आए बदलाव को परखा जा सकता है।

जीन उत्परिवर्तन की दर बता सकती है कि यह वायरस कब तक 'वाइल्ड' रहा है और इसकी शुरुआत कहां हुई? वुहान वायरस का जीनोम 29,093 बेस लंबा और बहुत हाल की उत्पत्ति है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ों में होने की संभावना है और उनसे यह दूसरे जानवरों तक फैला। वुहान में इन जानवरों का सेवन आम होने से इंसान भी उससे संक्रमित हो गए। इंसान में मिले इस वायरस का संस्करण 30 अक्टूबर के बाद और 29 नवंबर के पहले का होने का अनुमान है।

बीते दशक में जेनेटिक शोध में हुए तीव्र विकास ने क्रिस्पर जैसे नए उपकरणों को जन्म दिया है। सवाल है कि दुनिया एक नई बीमारी पर काबू पाने और इलाज ढूंढ पाने के लिए कितनी अच्छी तरह तैयार है? नॉवेल कोरोनावायरस इस तैयारी को परखने का एक मौका है।

कानाफूसी

बेहतर तालमेल के लिए

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, राज्य सभा में विपक्ष के नेता हैं जबकि अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के नेता हैं। चौधरी को प्रमुख विपक्षी दल के विधायी दल के नेता का दर्जा भी हासिल है। आजाद नई दिल्ली के 5, साउथ एवेन्यू लेन में रहते हैं जबकि चौधरी हुमायूं रोड पर रहते हैं जो साउथ एवेन्यू लेन से करीब 5 किलोमीटर दूर है। कई बार कांग्रेस नेताओं में यह चर्चा चलती है कि उन्हें राज्यसभा और लोकसभा में बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। अब सूत्रों की मानें तो चौधरी आजाद के बंगले के पास ही एक बंगले में रहने आ रहे हैं। जाहिर है ऐसे में दोनों नेताओं को पार्टी की संसदीय नीति पर चर्चा के लिए अधिक वक्त मिल सकेगा।

कहने का तात्पर्य?

हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की इस बात के लिए सराहना की गई कि उनके विभाग ने हरियाणा में कमाल का काम किया है। परंतु बाद में उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि कार्यक्रम में शामिल लोग अपना सिर खुजाते रह गए। जब मंत्री से पूछा गया कि क्या उनका मंत्रालय ऐसा ही काम बिहार में कर सकता है। गडकरी ने जवाब में कहा कि उनमें ऐसा करने की क्षमता नहीं है। लोगों के मन में यह सवाल बना रहा कि वह कहना क्या चाहते थे? उनके विभाग में वाकई क्षमता नहीं या उनका इशारा बिहार की मौजूदा सरकार की ओर है। बहरहाल, अधिकांश लोगों ने दूसरी संभावना को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है।

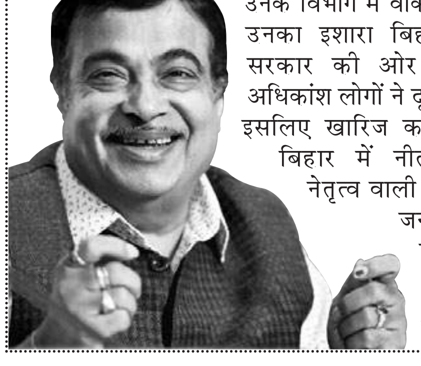

नितिन गडकरी

आपका पक्ष

सर्वजन हिताय हो आम बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही हैं जब वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की गति भी सुस्त है। बजट आर्थिक सुस्ती से निपटने और भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर सर्वजन हिताय वाला होना चाहिए। देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि और इससे संबंधित कार्य पर निर्भर हैं। अत: यह जरूरी है कि बजट में कृषि उत्पादन बढ़ाने, उन्नत तकनीक व आधुनिकीकरण और कृषि आय बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। उम्मीद है कि बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने, आयकर दरों को तर्कसंगत करने और रोजगार सृजन के उपायों की घोषणा हो सकती है।

मनोहरलाल उपाध्याय, इंदौर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी - *पीटीआई*

रोजगार सृजन जरूरी

इस आर्थिक सुस्ती के माहौल में घटते रोजगार को बढ़ाने वाले समुचित उपायों के लिए आम बजट में अलग निधि का प्रावधान करने की जरूरत है। महिलाओं को कर में छूट, किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाने के प्रावधान, करदाताओं की संख्या में इजाफा करने, औद्योगिक विकास के लिए मदों को बढ़ाने की आवश्यकता के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए विशेष मदों की जरूरत है।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, उज्जैन

किसान हित में पहल

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर अधिक व्यय करना चाहिए। किसानों पर व्यय करने की जरूरत है। किसानों को तकनीकी से जोड़ने पर बल देना चाहिए। किसान को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके इसके लिए वाणिज्य बैंकों को अधिक सहूलियत प्रदान की जानी चाहिए। सरकार को उद्योगपतियों एवं किसानों के बीच में पारस्परिक संबंध बेहतर बनाने के लिए व्यय करना चाहिए। ताकि उद्योगपति किसान से सीधे तौर पर कच्चा माल खरीद सकें।

उद्देश्य, गोरखपुर

महंगाई काबू में हो

आम बजट में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा, इसकी उम्मीद है। बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार बढ़ाने, आयकर की मौजूदा दरों में कुछ रियायत करने और कृषि क्षेत्र में किसान हितैषी योजनाओं को लाने की जरूरत है। ऐसी उम्मीद भी है कि सरकार इन समस्याओं पर विशेष ध्यान रखकर ही बजट पेश करेगी। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र, रियल एस्टेट क्षेत्र में भी सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसे देखते हुए आगामी बजट से यही उम्मीद है।

भूपेंद्र सिंह, पानीपत

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

चीनी उत्पादन पर अलग-अलग दावे

चीनी उत्पादन 17.5 प्रतिशत गिरावट के साथ 2.74 करोड़ टन रहने का अनुमान जताया

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 31 जनवरी

- इस्मा ने नवंबर 2019 में चीनी उत्पादन में 20 प्रतिशत गिरावट का अनुमान जताया था
- इस्मा का चीनी उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान फरवरी में आने की संभावना
- मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के दौरान महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन वर्ष 2018-19 में 1.07 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में 39 प्रतिशत गिरकर 65 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया
- कर्नाटक में पिछले साल के 44 लाख टन उत्पादन की तुलना में इस सत्र में उत्पादन करीब 23 प्रतिशत गिरकर 34 लाख टन का अनुमान जताया गया

चीनी उद्योग के एक घरेलू कारोबारी संगठन ने मौजूदा पेराई सत्र 2019-20 में देश का चीनी उत्पादन 2.74 करोड़ टन आंका है जो मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के अनुमान से 14 लाख टन अधिक है। इस्मा ने 2.6 करोड़ टन चीनी उत्पादन की संभावना जताई थी। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) के अनुसार मौजूदा सत्र में चीनी उत्पादन पिछले साल के 3.32 करोड़ टन की तुलना में करीब 17.5 प्रतिशत गिरकर 2.74 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

एआईएसटीए ने देश का चीनी उत्पादन 2.74 करोड़ टन आंका है जो इस्मा के 2.6 करोड़ टन चीनी उत्पादन अनुमान से 14 लाख टन अधिक है

नवंबर 2019 में इस्मा ने अपने शुरुआती पूर्वानुमान में चीनी उत्पादन में 20 प्रतिशत तक की तेज गिरावट का अनुमान जताया था। फरवरी में वर्ष 2019-20 के लिए चीनी उत्पादन का इसका दूसरा अग्रिम अनुमान आने की संभावना है।

एआईएसटीए ने उत्पादन में इस कमी के लिए मुख्य रूप से पिछले साल महाराष्ट्र के मराठावाड़ा क्षेत्र में सूखे और पश्चिमी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश की वजह से राज्य के उत्पादन में भारी गिरावट का हवाला दिया है। मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के दौरान राज्य का चीनी उत्पादन वर्ष 2018-19 में 1.07 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में 39 प्रतिशत गिरकर 65 लाख टन रहने का अनुमान है।

अब तक उत्पादित चीनी, चीनी उत्पादन के संभावित रुख, चीनी प्राप्ति की दर, पेराई के लिए गन्ने की उपलब्धता और बी-भारी शीरे से एथनॉल उत्पादन पर विचार करने के बाद ये अनुमान लगाए गए थे। बी-भारी शीरे से उत्पादित एथनॉल के कारण लगभग 10 लाख टन चीनी को समायोजित किया जाएगा। इस साल चीनी उत्पादन में आई कमी में इसका भी योगदान रहा है।

इसके अलावा कर्नाटक में पिछले साल के 44 लाख टन उत्पादन की तुलना में इस सत्र में उत्पादन करीब 23 प्रतिशत गिरकर 34 लाख टन रहने वाला है। हालांकि देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन 1.18 करोड़ टन से बढ़कर 1.2 करोड़ रहने की उम्मीद है। एआईएसटीए ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख चीनी कंपनियों ने अपनी एथनॉल क्षमता में इजाफा किया है या इजाफा करने की प्रक्रिया में है।

इस बीच एआईएसटीए ने संभावना जताई है कि घरेलू बाजार में कच्ची चीनी की कम उपलब्धता के परिदृश्य में चीनी निर्यात 45 लाख टन रहेगा। इससे पहले इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा था कि इस सत्र में चीनी निर्यात 50 लाख टन तक जाने की संभावना है।

अब तक मिलें अपनी अधिकतम स्वीकृत निर्यात मात्रा (एमएईक्यू) के मुकाबले 25 लाख टन निर्यात अनुबंध कर चुकी हैं। देश के प्रमुख निर्यात गंतव्य ईरान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देश आदि हैं।

कच्चा इस्पात उत्पादन रहा 6 करोड़ टन

भाषा
नई दिल्ली, 31 जनवरी

- अप्रैल-अक्टूबर 2019-20 के दौरान 6.43 करोड़ टन कच्चे इस्पात और 5.97 करोड़ टन तैयार इस्पात का उत्पादन हुआ

भारत ने अप्रैल-अक्टूबर 2019-20 के दौरान 6.43 करोड़ टन कच्चे इस्पात और 5.97 करोड़ टन तैयार इस्पात का उत्पादन किया है। संसद में आज पेश आर्थिक समीक्षा में यह जानकारी दी गई है। समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान इस्पात क्षेत्र की वृद्धि 5.2 प्रतिशत रही। एक साल पहले समान अवधि में वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत थी। संसद में पेश वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, '2018-19 में देश का कच्चा इस्पात उत्पादन 10.9 करोड़ टन पर था, जबकि चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक 6.43 करोड़ टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया गया है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।'

इसी प्रकार, तैयार इस्पात का उत्पादन वर्ष 2018-19 में 13.7 करोड़ टन रहा है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान 5.97 करोड़ टन तैयार इस्पात का उत्पादन किया गया है। समीक्षा में कहा गया कि रिजर्व बैंक के कंपनियों के प्रदर्शन पर अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की मांग की स्थिति कमजोर हुई है।

पेट्रोलियम उत्पाद, लौह अयस्क एवं इस्पात, मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपकरण कंपनियों का आर्थिक नरमी में काफी योगदान रहा।

नीति में सुधार से बढ़ा खनिज उत्पादन

खनिज उत्पादन क्षेत्र में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

सरकार की नीतिगत पहलों और सुधारों से देश के खनिज उत्पादन में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में यह बात सामने आई है। समीक्षा के अनुसार खनिज उत्पादन क्षेत्र में 2018-19 की तुलना में मात्रा के आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। खनिज उत्पादन क्षेत्र में इस उल्लेखनीय वृद्धि का कारण सरकार की नीतियों में सुधार करना है। देश में 95 तरह के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। इसमें कोयला और लिग्नाइट समेत चार हाइड्रोकार्बन, पांच परमाणु खनिज, 10 धात्विक खनिज, 21 गैर-धात्विक खनिज और 55 अन्य प्रकार के खनिज हैं। यह खनिज विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं।

समीक्षा के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कच्चा कोयला का उत्पादन 8.1 प्रतिशत बढ़ा है। 2018-19 में कुल 73.04 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था। जबकि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में 41.05 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हो चुका है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 की राष्ट्रीय वार्षिक आय में खनन क्षेत्र ने 2.38 प्रतिशत की सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) का योगदान दिया किया था।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोयला उत्पादन में वृद्धि देखी गई और बाद में इसमें गिरावट रही। देश में कोयले की मांग और आपूर्ति के अंतर की पूर्ति कोयला के आयात से की जा रही है। वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष के शुरुआती छह माह में कुल 12.62 करोड़ टन कोयले का आयात किया गया। *भाषा*

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 31	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,722.5	-1.1	2,017.9	5.2
Copper	5,621.0	-3.5	6,292.0	2.6
Nickel	12,535.0	-25.5	13,452.9	-22.4
Lead	1,836.0	-16.9	2,158.1	0.0
Tin	16,275.0	-2.8	17,166.5	-3.4
Zinc	2,235.5	-12.1	2,536.4	-7.3
Gold ($/ounce)	1,579.8*	4.4	1,770.8	4.5
Silver ($/ounce)	17.9*	-1.4	20.2	-1.4
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	57.4*	-3.6	57.9	-4.5
Natural Gas ($/mmBtu)	1.8*	-30.4	1.8	-30.0
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	197.2	9.6	290.8	-3.0
Maize	186.4*	2.4	273.1	-2.7
Sugar	413.3*	22.1	487.5	-1.6
Palm oil	700.0	18.6	1,135.1	22.7
Rubber	1,453.1*	1.0	1,891.8	7.3
Coffee Robusta	1,302.0*	0.7	1,772.7	-7.2
Cotton	1,514.6	6.6	1,580.2	0.8

* As on Jan 31, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.4& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	59.5	35069
Oil and Oilseeds	161.7	85365
Spices	0.5	9
Metal(Jan 30)		
Metal- non ferrous	5055.5	44760
Metal- precious	16297.4	358
Oil and gas(Jan 30)		
Gas	2399.1	55609
Oil	15121.8	2777

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	226.7	136700
Grains	134.9	94400
Oil and Oilseeds	421.9	463030
Others	169.9	66375
Pulses	34.2	35565
Spices	42.2	22928

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Silver Mini (Feb 28)	46934.0	3.0
Silver (Mar 05)	46914.0	3.0
Silver Micro (Feb 28)	46932.0	3.0
Gold (Feb 05)	40975.0	1.5
Gold Mini (Feb 05)	40897.0	1.4
Nickel (Jan 31)	946.9	0.7
Losers (* % Change)		
Kapas (Feb 28)	1038.0	-3.0
Cardamom (Feb 14)	3800.4	-2.9
Natural Gas (Feb 25)	131.3	-2.5
Crude Oil (Feb 19)	3723.0	-2.2
Aluminium Mini (Jan 31)	145.4	-1.7
Zinc (May 29)	179.7	-1.1

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1748.5	1.0
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	7080.0	0.7
Guar Seed 10 (Feb 20)	3972.0	0.6
Jeera Unjha (Mar 20)	14100.0	0.5
Losers(* % Change)		
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1075.0	-1.0
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	847.8	-1.0
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5956.0	-0.9
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4109.0	-0.8
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1783.0	-0.6
Chana-Bikaner (Mar 20)	3988.0	-0.2
Coriander-Kota (Apr 20)	6498.0	-0.2
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3938.0	-0.1

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Copper Mum (Jan 31)	433.3	2.3
Alumini-Mumbai (Jan 31)	145.4	2.3
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46932.0	1.2
Silver Ahm (Mar 05)	46914.0	1.1
Zinc Mumbai (May 29)	179.7	1.0
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1038.0	0.8
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1197.7	-10.0
Lead Min Mumbai (Jan 31)	145.9	-4.7
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3800.4	-1.9
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	175.2	-1.5
Aluminium Mum (May 29)	140.5	-1.1
Lead Mum (May 29)	151.6	-1.0

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	745.3	1.7
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	19130.0	1.0
Moong-Merta City (Feb 20)	7794.0	0.9
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1888.0	0.6
Bajra-Delhi (Feb 20)	1888.0	0.4
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3186.0	0.3
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1748.5	-18.7
Jeera Unjha (Mar 20)	14100.0	-6.6
Coriander-Kota (Apr 20)	6498.0	-2.2
Soy Bean Indore (Feb 20)	4084.0	-1.6
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	7080.0	-1.0

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	106....................(106)
Aluminium ingots /kg	144....................(144)
Brass sheet cutting /kg	325....................(325)
Brass utensil scraps/kg	305....................(300)
Copper heavy scrap /kg	415....................(415)
Copper utensil scraps/kg	391....................(394)
Copper wire bar /kg	449....................(447)
Lead ingots /kg	154....................(154)
Nickel Cathodes /kg	960....................(955)
Tin slabs /kg	1225..................(1235)
Zinc slabs /kg	181....................(181)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10236................(10236)
DCH - 32 /Qtl	11332................(11389)
Jaydhar /Qtl	9758..................(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11107................(11164)

Source:Cotton Association of India

Oil	............Mumbai
Castor FSG /10kg	848....................(865)
Castor Comm /10kg	838....................(855)
Ricebran oil/10kg	-(820)
Groundnut oil /10kg	1140..................(1140)
Linseed oil /10kg	-(935)
Karanji /10kg	-(800)
Palm oil /10kg	835....................(840)
Sunflower exp ref /10kg	880....................(880)
Sunflower oil exp /10kg	850....................(855)
Soyabean ref / 10kg	865....................(870)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3372-3585 ....(3372-3585)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	....
NYSE Crude	52.26..................(52.14)
Brent Crude (UK)	57.11..................(57.97)
Brent Crude (WTI)	52.14..................(52.14)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.83....................(1.83)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	298.11................(307.71)
Naptha spot /Rs/MT	45170.................(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.................(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.................(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40628.................(40684)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40791.................(40848)
Silver.999/ kg	46395.................(46170)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19068.85	18943.35
Alumini-Mumbai (M)	1 K	143.05	142.10
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1850.00	1880.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1881.65	1876.65
Barley Jaipur (N)	1 Q	2150.00	2150.00
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3850.00	3857.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4090.00	4051.40
Castor Seed-Kadi (N)	X	4030.00	4052.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4088.75	4077.35
Chana Delhi (N)	1 Q	4314.60	4300.00
Chana-Akola (N)	X	4000.00	3995.00
Coriander-Gondal (N)	X	6400.00	6406.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6562.50	6516.65
Coriander-Kota (N)	1 Q	6686.25	6643.65
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1928.40	1891.30
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1958.35	1928.35
Cotton-Kadi (N)	1 B	19027.00	19027.00
CPO-Kandla (M)	10 K	768.80	765.50
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	745.15	732.75
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	750.00	732.50
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	907.65	908.05
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1553.40	1554.10
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3462.95	3461.90
Gold Ahm (M)	10 G	40717.00	40694.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32705.00	32686.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4081.00	4077.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7158.35	7155.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3941.65	3967.50
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3950.00	3925.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1095.95	1086.35
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	103.35	104.70
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	15600.00	15500.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	15233.35	15100.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	863.00	861.10
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1029.30	1028.05
Kapas-Rajkot (N)	X	1035.25	1028.60
Lead Mum (M)	1 K	152.75	153.15
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1900.00	1921.25
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2228.15	2250.45
Maize-Erode (N)	X	1920.00	1912.90
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2228.15	2250.45
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2015.00	2012.50
Maize-Sangli (N)	X	1942.70	1949.50
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4725.00	4712.50
Moong-Merta City (N)	1 Q	7768.75	7727.80
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4385.50	4359.75
Nickel Mumbai (M)	1 K	952.50	955.90
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3175.00	3175.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3213.00	3202.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	333.00	331.80
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33669.25	33433.35
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	850.00	840.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	750.00	760.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1916.65	1900.85
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5318.35	5310.80
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	829.15	810.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	876.55	872.45
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	876.60	869.95
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	887.50	882.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13600.00	13500.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13583.00	13492.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46116.00	46383.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4182.00	4149.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4095.25	4095.25
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4242.00	4242.00
Soy Bean-Akola (N)	X	4141.00	4146.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33311.00	33100.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	877.00	874.20
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	32020.00	32000.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32230.00	32290.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	29060.00	29220.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3225.00	3225.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3390.50	3409.50
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3289.55	3268.35
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3476.20	3476.20
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3290.00	3284.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3150.00	3131.65
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5985.00	5967.85
Wheat Delhi (N)	1 Q	2210.00	2210.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2170.50	2155.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2187.50	2187.50
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2115.00	2130.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2203.35	2193.35
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5700.00	5600.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5700.00	5700.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	179.15	177.90

* as on Jan 30, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (शुक्रवार)

कृषि जिंस

Name Exchange (Units) / Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19160, 19400, 19100, 19170	1301	141	1820
Feb 28	19450, 19520, 19370, 19430	3036	525	27474
Mar 31	19780, 19800, 19650, 19700	689	124	4809
Apr 30	20000, 20000, 19960, 19980	21	4	238
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1790, 1807, 1753, 1783	65510	4222	55110
Mar 20	1812, 1828, 1770, 1796	34150	2643	59360
Apr 20	1841, 1855, 1802, 1821	4480	413	14440
May 20	1877, 1877, 1831, 1841	720	68	3940
Kapas MCX(20 K)				
Feb 28	1038, 1038, 1038, 1038	4	1	-
Apr 30	1088.5, 1088.5, 1070.5, 1074	348	73	724
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1086, 1088, 1068.5, 1075	1820	927	3850
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1715, 1748.5, 1715, 1748.5	40	4	2030
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3966, 3990, 3942, 3972	21335	2086	57145
Mar 20	4004, 4038, 3992, 4020	12365	1045	33100
Apr 20	4046, 4080, 4042, 4060	100	18	235
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3950, 3950, 3902, 3938	5215	579	15100
Mar 20	3962, 3966, 3914, 3962	4975	604	16225
Apr 20	3968, 3988, 3938, 3980	475	92	3505
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	774.7, 774.7, 771.4, 771.8	2420	143	13080
Feb 28	741.7, 748, 740.1, 744.3	13040	864	50540
Mar 31	736.1, 739.1, 734.5, 736.6	1260	84	19040
Apr 30	730, 730, 729.8, 730	100	10	2470
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1201, 1211.4, 1196, 1203.6	249.12	589	181.08
Mar 31	1204.4, 1212.2, 1193.6, 1196.7	48.96	127	37.08
May 29	1179, 1179, 1179, 1179	0.36	1	3.6
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4126, 4141, 4090, 4109	10980	766	13460
Apr 20	4150, 4166, 4112, 4122	9450	746	14030
May 20	4172, 4172, 4122, 4131	1570	111	3290
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	849.8, 854.6, 846.8, 847.8	9635	980	38825
Mar 20	833.2, 836.2, 830.8, 831.8	6925	740	45435
Apr 20	826.4, 829.8, 823, 824.8	1065	153	4625
May 20	823.4, 825.8, 818.2, 825.8	65	8	115
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4060, 4092, 4058, 4084	18155	2134	107980
Mar 20	4044, 4064, 4038, 4050	13675	1766	122980
Apr 20	4032, 4058, 4028, 4044	2275	355	64035
May 20	4040, 4056, 4032, 4044	355	52	13240
Jun 19	4070, 4070, 4060, 4060	20	3	180
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	7032, 7127, 7015, 7080	12260	1167	21850
Mar 20	7128, 7215, 7100, 7163	11255	938	44095
Apr 20	7226, 7297, 7226, 7254	355	25	430
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3994, 4004, 3970, 3988	6320	516	23590
Apr 20	3990, 3995, 3955, 3983	1840	167	9460
May 20	4000, 4015, 4000, 4009	400	33	2440
Jun 19	4041, 4041, 4041, 4041	10	1	30
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3800.1, 3801, 3800, 3800.4	0.3	3	4.8
Mar 13	3800, 3850, 3800, 3830.4	0.9	9	3.6
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6520, 6564, 6486, 6498	1040	89	9270
May 20	6485, 6515, 6472, 6500	110	11	540
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	14085, 14190, 13780, 14100	1374	422	2094
Apr 20	13785, 13900, 13505, 13780	573	171	1599
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6036, 6052, 5930, 5956	800	157	4985
Apr 20	6062, 6062, 5856, 5892	470	90	4315

धातु

Name Exchange (Units) / Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	140.35, 142.35, 140.05, 141.2	18	7	3
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	147.25, 148.45, 139.6, 139.95	143	112	350
Feb 28	139.6, 140.05, 138.45, 138.65	4134	2765	5065
Mar 31	140.1, 140.3, 139.2, 139.35	167	128	282
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	435.55, 437, 430, 436.45	187.5	18	77.5
Feb 28	427.9, 429.4, 427, 428.25	13997.5	4636	14315
Mar 31	430.2, 431, 429, 429.45	282.5	98	795
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	147, 148.15, 147, 147.8	5384	3343	6113
Mar 31	149.4, 149.4, 147.7, 148.2	67	63	284
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	951, 952, 946, 949.1	10.5	6	76.5
Feb 28	938.1, 953.3, 938.1, 950.1	11371.5	6913	3651
Mar 31	939.6, 950.2, 939, 948.5	93	61	108
Zinc MCX(1 K)				
May 29	177.65, 180.75, 177.25, 178.55	3	3	21
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	176.1, 177.75, 173, 174.3	146	106	579
Feb 28	175.65, 175.85, 174.25, 174.9	18995	11306	19844
Mar 31	176.3, 176.3, 174.8, 175.25	631	439	1523
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	41014, 41014, 40571, 40751	0.5	405	0.59
Apr 03	40881, 40898, 40639, 40816	5.27	4507	19.24
Jun 05	40795, 41024, 40728, 40941	0.46	421	4.3
Gold Guinea MCX(8 G)				
Jan 31	32438, 32438, 32300, 32313	0	9	0
Feb 28	32250, 32380, 32180, 32339	0	270	0.01
Mar 31	32290, 32390, 32265, 32346	0	46	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Feb 05	40490, 40799, 40490, 40750	0.06	310	0.08
Mar 05	40750, 40750, 40513, 40678	0.81	6035	0.79
Apr 03	40700, 40862, 40650, 40779	0.14	1194	0.25
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Jan 31	4034, 4046, 4034, 4041	0	14	0
Feb 28	4029, 4030, 4015, 4028	0	1049	0.01
Mar 31	4045, 4051, 4034, 4047	0	172	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46520, 46637, 46350, 46490	226.5	6307	264.24
May 05	47108, 47135, 46875, 47003	5.73	139	18.96
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46832, 46832, 46350, 46510	30.16	21224	25.57
Apr 30	47296, 47296, 46910, 47026	2.45	1806	4.96
Jun 30	47550, 47550, 47290, 47420	0	2	0.14
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46650, 46668, 46362, 46508	87.7	13993	47.21
Apr 30	47200, 47200, 46896, 47039	3.01	559	5.58

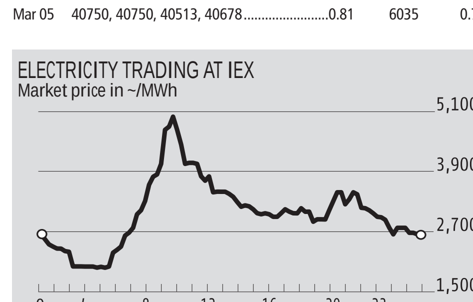

तेल एवं गैस

Name Exchange (Units) / Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	131.6, 132.4, 130.3, 131.7	58128mb	25168	58095mb
Mar 26	135.5, 135.8, 134.3, 135.4	1960mb	1051	4410mb
Apr 27	140.1, 140.2, 138.4, 139.8	51mb	37	101mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3739, 3817, 3734, 3757	14781bl	86001	3329bl
Mar 19	3754, 3834, 3754, 3777	413bl	3289	228bl
Apr 20	3815, 3838, 3797, 3825	1bl	6	2bl

सायं सत्र (गुरुवार)

कृषि जिंस

Name Exchange (Units) / Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19220, 19280, 19180, 19220	264	26	2577
Feb 28	19460, 19590, 19440, 19480	3754	576	27219
Mar 31	19760, 19850, 19730, 19840	408	60	4694
Apr 30	20060, 20100, 20060, 20080	38	5	230
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1091, 1091, 1084, 1085	412	80	728
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1092, 1092, 1084, 1086	1321	735	3604
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	778.6, 782.5, 774.1, 774.7	4570	261	14230
Feb 28	757.6, 759.5, 745.3, 747.5	29680	2197	50520
Mar 31	751.1, 754, 737.3, 740.1	10240	777	18780
Apr 30	739.7, 742.5, 732, 733.4	3280	240	2420
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	857.8, 859, 848.4, 852.4	22245	2601	39830
Mar 20	843, 843.8, 830, 832.6	18195	2000	45565
Apr 20	840, 840, 823, 824.4	1285	218	4605
May 20	831, 831, 823.6, 829.4	45	8	105

धातु

Name Exchange (Units) / Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	147.95, 147.95, 144.15, 145.4	91	52	416
Feb 28	139.35, 140.4, 139, 139.6	8903	5477	4211
Mar 31	140.15, 140.6, 139.65, 140	179	170	217
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	429.2, 435, 429.2, 433.3	170	13	200
Feb 28	428.75, 429.35, 425.9, 426.5	31767.5	10971	12077.5
Mar 31	431.6, 431.6, 427.55, 428.3	517.5	195	642.5
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	145.7, 146, 145.7, 145.9	6	6	256
Feb 28	146.75, 147.65, 145.6, 147.25	15129	9677	4972
Mar 31	147.45, 148.1, 146.75, 147.7	422	347	258
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	948.4, 960.5, 943, 946.9	24	7	85.5
Feb 28	936, 943.8, 931.5, 939.4	27550.5	16681	2674.5
Mar 31	931.3, 941, 931, 936.9	174	114	93
Zinc MCX(1 K)				
May 29	178.85, 180.8, 178.35, 179.65	5	5	21
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	175.6, 175.6, 175.1, 175.2	132	43	1084
Feb 28	177.4, 177.45, 175.1, 175.3	38697	23636	16387
Mar 31	177.7, 177.85, 175.5, 175.65	1462	1129	1153
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	40486, 41068, 40472, 40975	5.91	4906	0.81
Apr 03	40741, 41100, 40683, 41073	14.09	12005	19.18
Jun 05	40800, 41188, 40800, 41168	1.27	1058	4.15
Gold Guinea MCX(8 G)				
Jan 31	32328, 32428, 32265, 32354	0	14	0
Feb 28	32300, 32450, 32252, 32423	0.01	724	0.01
Mar 31	32290, 32450, 32232, 32449	0	83	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Feb 05	40400, 40990, 40400, 40897	0.5	3479	0.12
Mar 05	40470, 40950, 40470, 40920	1.92	16045	0.78
Apr 03	40656, 41068, 40656, 41039	0.29	2287	0.25
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Jan 31	4029, 4070, 3969, 4060	0	39	0
Feb 28	4012, 4046, 4012, 4040	0.01	2566	0.01
Mar 31	4020, 4075, 4020, 4061	0	534	0
Apr 30	4030, 4060, 4030, 4057	0	14	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45740, 46966, 45740, 46914	928.98	25770	243.84
May 05	46388, 47440, 46360, 47385	15.66	491	20.7
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45690, 46995, 45690, 46932	113.76	78188	20.27
Apr 30	46198, 47475, 46198, 47418	12.16	8390	4.89
Jun 30	46900, 47900, 46720, 47627	0.06	53	0.14
Aug 31	47996, 48000, 47996, 47998	0	3	0.02
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45655, 46997, 45655, 46934	318.18	49598	37.48
Apr 30	46428, 47479, 46362, 47419	11.93	2166	5.31
Jun 30	47209, 47209, 47209, 47209	0.01	1	0.04

तेल एवं गैस

Name Exchange (Units) / Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	134.6, 135.6, 130.7, 131.3	175944mb	76137	51366mb
Mar 26	137.8, 138.9, 135, 135.5	4426mb	2842	4160mb
Apr 27	142.6, 143.7, 140, 140.3	165mb	127	83mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3799, 3799, 3712, 3723	39402bl	222886	2533bl
Mar 19	3796, 3804, 3735, 3746	918bl	7920	241bl
Apr 20	3820, 3820, 3760, 3777	2bl	16	2bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd
Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas
For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel
Market price in Rs.

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

कोरोना पर स्वास्थ्य इमरजेंसी

चीन में अब तक कोरोनावायरस के संक्रमण से 213 से अधिक लोगों की मौत हो गई है जबकि 9,800 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में हैं

कोरोनावायरस के संक्रमण की वजह से फिलीपींस में स्कूली छात्राओं की हो रही जांच

दुनिया भर में बढ़ा संकट

- **विमानन कंपनियों ने चीन जाने वाली उड़ानें रद्द कीं या उनकी संख्या घटाई है**
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा कर दी है**
- **वुहान से कई देशों के नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया जारी**
- **बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन के संयंत्रों में उत्पादन प्रक्रिया रोकी**

चीन समेत दुनिया के कई देशों में फैले खतरनाक कोरोनावायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा वैश्विक आपात की घोषणा करने के एक दिन बाद अमेरिका और अन्य देशों ने शुक्रवार को चीन की यात्रा पर ज्यादा सख्ती कर दी। वहीं कारोबारी चीन में कोरोनावायरस की वजह से आपूर्ति की दिक्कतों से जूझ रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ ने वायरस को नियंत्रित करने की चीन की कोशिशों की तारीफ की जिसके बाद शेयर बाजार में थोड़ी स्थिरता दिखी। हालांकि वुहान के मेयर ने कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकना बेहद गंभीर और जटिल काम है। वहीं चीन के वुहान कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने कहा कि चीन के बाकी हिस्से और दुनिया में वायरस का असर कम होगा अगर जल्द से जल्द कदम उठाया जाएगा।

वहीं जर्मनी के शोध मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि कुछ महीने में कोरोनावायरस का टीका तैयार किया जा सकता है।

चीन में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 213 हो गई है और संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या 9,800 से अधिक हो गई है। हालांकि इस वायरस के संक्रमण से चीन के बाहर किसी के मरने की खबर नहीं मिली है लेकिन 23 अन्य देशों में 131 मामलों की पुष्टि की गई है।

अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे एशियाई देशों की यात्रा न करें। कोरोनावायरस का पहला मामला चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में सामने आया। चीन ने भी अपने नागरिकों को विदेश यात्राएं नहीं करने की सलाह दी है।

जापान ने भी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे चीन तक की गैर-जरूरी यात्रा न करें। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने चीन से आने वाले सभी यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की गुजारिश की है जबकि ब्रिटेन में कोरोनावायरस के संक्रमण के दो मामले की पुष्टि हुई है। सिंगापुर ने कहा कि चीन के यात्रियों को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और चीन के पासपोर्ट धारकों की वीजा रद्द की जा रही है। यह प्रतिबंध शनिवार से लागू होगा।

इटली की सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा करने का फैसला किया है और चीन से जुड़ी सभी विमान सेवाएं रोक दी गई हैं। इटली ने देश में आए दो चीनी पर्यटकों के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद चीन जाने वाले विमानों के संचालन पर रोक लगा दिया गया।

महामारी बढ़ने पर दुनिया भर की आपूर्ति शृंखला प्रभावित होगी और जो कंपनियां प्रभावित क्षेत्र में काम कर रही हैं उन्हें उत्पादन घाटे का सामना करना पड़ सकता है। हुंडई मोटर्स ने कहा कि इसने दक्षिण कोरिया के एसयूवी संयंत्र में इस सप्ताहांत काम रोकने की योजना बनाई है। गूगल और स्वीडन की आइकिया ने चीन में अपना काम बंद कर दिया है।

एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज और लुफ्थांसा जैसी शीर्ष विमानन कंपनियों ने चीन तक सेवाएं निलंबित कर दी हैं। वहीं इंडोनेशिया में चीन के नियंत्रण वाले एक विशाल औद्योगिक परिसर में कार्यरत 40 हजार से अधिक कर्मचारियों को परिसर में ही रोक दिया गया है। परिसर में कार्यरत कर्मचारियों से कहा गया है कि वे लिखित अनुमति के बिना इससे न तो बाहर जाएं और न ही इसमें प्रवेश करें।

चीन ने घोषणा की कि वह कोरोनावायरस से प्रभावित हुबेई प्रांत के निवासियों को विदेश से वापस घर लाने के लिए चार्टर विमान भेजेगा। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हुबेई प्रांत के नागरिकों को विदेश में सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के चलते वापस लाया जाएगा।

एजेंसियां

2 रुपये किलो आटा, सीलिंग से राहत का वादा

बीएस संवाददाता

भाजपा का संकल्प पत्र

- **गरीबों को 2 रुपये किलो में गेहूं का आटा, हर घर को नल से जल**
- **10 लाख नये रोजगार, कचरा व प्रदूषण मुक्त दिल्ली और विकास का वादा**
- **दिल्ली में भी आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि योजना लागू करने का वादा**

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में जहां एक ओर गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं का आटा, कारोबारियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड व सीलिंग से निजात, समृद्ध दिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना, 10 लाख नये रोजगार, हर घर को नल से स्वच्छ पानी का वादा किया है, दूसरी ओर दिल्ली सरकार द्वारा लागू नहीं की गई केंद्र सरकार की आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास और किसान सम्मान निधि योजना को सत्ता में आने पर लागू करने का वादा किया है।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनने पर दिल्ली का विकास बुलेट ट्रेन की रफ्तार से होगा। संकल्प पत्र में व्यापार व उद्योग के मुद्दों को अहमियत देते हुए 10 लाख कारोबारियों की दुकानों और कार्यालयों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करने का वादा किया गया है। साथ ही सीलिंग से राहत के लिए नियम व कानून में बदलाव, पंजीकृत लघु उद्यमियों को दुर्घटना बीमा, दिल्ली के बाजारों में और सुविधाओं के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में समस्या निवारण केंद्र खोलने, एकल खिड़की मंजूरी तंत्र, बिजली की औद्योगिक दरों की समीक्षा, दिल्ली को विश्वस्तरीय सेवा हब बनाने का वादा किया है। भाजपा ने बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए अगले पांच साल में 10 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही रिक्त पदों को भरने और अनुबंध कर्मियों को नौकरी की गारंटी दी है। दिल्ली में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये का विशेष स्टार्टअप ऐंड इनोवेशन फंड का वादा भी किया है। संकल्प पत्र में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से समृद्ध दिल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत बेहतर सड़क, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज आदि बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का आश्वासन है। भाजपा ने कॉलेज में प्रवेश लेने वाली आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की छात्राओं को मुफ्त ई-स्कूटी का भी वादा किया है। सकल्प पत्र में यमुना की सफाई, दिल्ली को कचरे के ढेर और प्रदूषण से मुक्ति, महिला सुरक्षा, रेहडी-पटरी वालों का नियमितीकरण, 10 नये कॉलेज व 200 नये स्कूल, लोकपाल कानून, बिजली तारों को भूमिगत करने, टैलेंट हंट के लिए सहायता, सफाई कमिर्यों का बकाया भुगतान आदि वादे किए गए हैं। बिजली-पानी सब्सिडी के सवाल पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बिजली-पानी के संदर्भ जो रियायतें अभी दी जा रही हैं, वो जारी रहेंगी।

एयर इंडिया का विमान भेजा गया वुहान

चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप के मद्देनजर वुहान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एयर इंडिया का 423 सीटों वाला बी747 विमान शुक्रवार को दिल्ली हवाई अड्डे से अपराह्न एक बजकर 20 मिनट पर रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि विमान में राममनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के पांच चिकित्सक और एक पैरामेडिकल कर्मी सवार थे।

उन्होंने बताया कि इस विमान से करीब 400 भारतीयों को वापस लाया जाना है। विमान के उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि वुहान से भारतीयों को वापस लाने के लिए एक अन्य विशेष उड़ान शनिवार को दिल्ली हवाई अड्डे से रवाना हो सकती है।

गुजरात सरकार ने चीन में रह रहे राज्य के 200 से अधिक छात्रों की जानकारी विदेश मंत्रालय और चीन में भारतीय दूतावास को दी है। ये छात्र चीन में कोरोना वायरस फैलने के बाद वापस भारत लौटना चाहते हैं।

भारत ने शुक्रवार को कहा कि कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे के बीच निजी सुरक्षा सामानों मसलन मास्क और कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है।

आईटीबीपी ने बनाया केंद्र

सीमा प्रहरी आईटीबीपी ने कोरोनावायरस से प्रभावित संदिग्ध लोगों को बुनियादी चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए दिल्ली में 600 बिस्तरों वाला पृथक केंद्र तैयार किया है। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने बताया कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) कैंप में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इस केंद्र में 25 डॉक्टरों की एक टीम मौजूद रहेगी। पांडे ने बताया कि संक्रमण के संदिग्ध मरीज के लिए बनाए गए पृथक केंद्र में बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एयर इंडिया के विशेष विमान से चीन के हुबेई प्रांत से लाए जा रहे लोगों को हवाई अड्डे पर प्रथम स्तरीय जांच के बाद यहां लाया जाएगा।

इस विमान से करीब 400 भारतीयों को वापस लाने की संभावना है

भारतीय सेना ने भी चीन के हुबेई प्रांत में कोरोनावायरस फैलने के मद्देनजर वहां से वापस लाए जा रहे करीब 300 भारतीय छात्रों को रखने के लिए दिल्ली के पास मानेसर में एक पृथक केंद्र बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने यह केंद्र मानेसर के पास बनाया है जहां छात्रों पर दो सप्ताह तक कुशल चिकित्सकों और सहायक कर्मियों की एक टीम द्वारा किसी संक्रमण को लेकर नजर रखी जाएगी। केरल में स्वास्थ्य अधिकारियों ने नोवेल कोरोनावायरस से संक्रमित पाई गई एक छात्रा को शुक्रवार को जनरल अस्पताल से त्रिशूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार ने कोरोनावायरस से प्रभावित क्षेत्रों से लौटने वाले लोगों के परिवारों से शादी स्थगित करने को कहा है। कोरोनावायरस से संक्रमित होने के संदेह में छह लोगों को नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के एक अलग वार्ड में निगरानी में रखा गया है और उनकी जांच रिपोर्टों का इंतजार किया जा रहा है। चीन से लौटे ओडिशा के कंधमाल जिले से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल के एक छात्र को खांसी और जुकाम के चलते शुक्रवार को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया है। *एजेंसियां*

भारतीयों का बढ़ता जलवा

पृष्ठ 1 का शेष

दुनिया की अग्रणी आईटी फर्मों की कमान संभालने वाले दिग्गजों में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा और एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण प्रमुख हैं। कृष्ण से कंपनी की उम्मीदें भी काफी होंगी, क्योंकि अन्य भारतीय मूल के सीईओ ने अपनी-अपनी फर्मों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और उनका मूल्यांकन भी ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया है।

विश्लेषकों के अनुसार आईबीएम धीरे-धीरे अपना ध्यान आईटी सेवा प्रदाता से हटाकर क्लाउड प्रदाताओं जैसे एमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर पर काम करने की है। आईबीएम सेवा क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी आधारित कारोबार में वृद्धि पर ज्यादा ध्यान दे रही है।

बेंगलूरु की एचआर सर्च फर्म के कार्याधिकारी ने कहा, 'बड़ी तकनीकी कंपनियां भारतीय सीईओ के साथ सफलता हासिल कर रही हैं। कृष्ण की पदोन्नति भी इसी के अनुरूप है। बेहतरीन तकनीकी पृष्ठभूमि वाले भारतीय इंजीनियर को आईटी फर्म के लिए अच्छा माना जाता है।'

कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और क्रिकइन्फो के सह-संस्थापक विशाल मिश्रा कृष्ण को करीब 20 साल से जानते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से आईबीएम में काम करने वाले कृष्ण बेहद कार्यकुशल हैं। मिश्रा अपने स्नातक के समय को याद करते हैं जब वह सोच रहे थे कि कोलंबिया ज्वॉइन करूं या आईबीएम। उन्होंने कहा वह सलाह के लिए कृष्ण के पास गए और उन्होंने उन्हें सलाह दी। वह अगर चाहते तो वह आईबीएम ज्वॉइन कर सकते थे लेकिन उन्होंने सही सलाह दी।

भारत आईबीएम के लिए बड़ा बाजार है और यहां उनके कर्मचारियों की संख्या करीब एक लाख है। 2018-19 में आईबीएम इंडिया का राजस्व 27,279 करोड़ रुपये रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2 फीसदी कम रहा। इस दौरान कंपनी का शुद्ध मुनाफा 2017-18 की तुलना में 12 फीसदी घटकर 2,426 करोड़ रुपये रहा।

आईटी आउटसोर्सिंग सलाहकार और पारीख कंसल्टिंग के संस्थापक पारीख जैन ने कहा, 'भारत आईटी सेवा का बड़ा बाजार है और आईटी दिग्गजों के कर्मचारियों की अच्छी खासी हिस्सेदारी देश है, जो उनकी आपूर्ति का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में अरविंद कृष्ण जो खुद आईटी दिग्गज हैं, की अगुआई में आईबीएम क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों और नए बाजारों में अगले चरण कके विकास की संभावना देख सकती है।'